दैनिक

भारत देश हमारा

मुख्य सम्पादक - जगजीत सिंह दर्दी | सम्पादक: अमृतपाल सिंह | DAILY BHARAT DESH HAMARA NEW DELHI

आरएनआई नं. 57282/1994 | वर्ष 31 | अंक 162 | नई दिल्ली | शनिवार 13 जून, 2026 | मूल्य एक रुपया | कुल पृष्ठ: 8 | फोन 97111 01161 | ईमेल : bharatdeshdelhi@gmail.com

राजस्थान की प्रख्यात मांड गायिका गवरी देवी का निधन

जयपुर, 12 जून (निस) राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का 98 वर्ष की आयु में गुरुवार देर शाम निधन हो गया। लगभग आठ दशक तक मांड गायन की परंपरा को जीवंत रखने वाली गवरी देवी अंतिम समय तक सक्रिय और स्वस्थ रहीं। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को सर्वोदय नगर में किया गया।

आशाराम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सरेंडर करने के आदेश

अहमदाबाद 12 जून (निस)अपने आश्रम की युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आशाराम को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए दायर अपनी याचिका वापस ले ली

नाविकों की मौत पर राहुल बोले-मोदी कंप्रोमाइज्ड पीएम देश के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते

नई दिल्ली 12 जून (निस) कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वाणिज्यिक जहाज पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत की घटना को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि कंप्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इन बेटों की जान लेने वालों को नाराज करने की इनमें न हिम्मत है, न ताकत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट में, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अन्तरराष्ट्रीय जल (क्षेत्र) में तीन दिन में तीन जहाजों पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो गई। और हमारे कंप्रोमाइज्ड (दबाव में आ चुके) पीएम... एक शब्द तक नहीं कहा। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है। लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाएं। राहुल ने कहा, अगले हफ्ते जी 7 में, हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद, मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे -- मगर, उन तीन भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। कांग्रेस नेता ने कहा, कंप्रोमाइज्ड पीएम (प्रधानमंत्री) भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें न हिम्मत है, न ताकत। कांग्रेस ने अमेरिका की लापरवाही भरी सैन्य कार्रवाइयों की बृहस्पतिवार को निंदा की थी, और सरकार से इस मामले में जवाबदेही तय करने के लिए राजनयिक कदम उठाने की मांग की। विपक्ष दल ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी व्यक्तिगत घनिष्ठता को बार-बार एक कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रदर्शित करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, जब यह संबंध भारतीय नागरिकों के जीवन और हितों की रक्षा करने में विफल हो जाए।

भारत ने बृहस्पतिवार को कहा था कि पिछले चार दिनों में ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले तीन वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी सेना ने हमला किया, जिसमें तीन भारतीयों की मौत हो गई। बृहस्पतिवार को एक और जहाज जलवीर पर हमला हुआ, जो गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाला टैंकर था और जिस पर 20 भारतीय सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सेटेबेलो, मैरीवेक्स और जलवीर पर हुए तीन अलग-अलग हमले अमेरिकी नौसेना की ओर से किए गए थे।

निशानेबाज एवं कोच जसपाल राणा का हृदयगति रुकने से निधन-खेल जगत में शोक की लहर, पीएम ने जताया शोक

नई दिल्ली 12 जून (संजय बंसल) भारतीय खेल जगत के लिए शुक्रवार का दिन एक बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाली खबर लेकर आया। देश के महान निशानेबाज और विख्यात कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया है। पिछले सप्ताह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। राष्ट्रीय राइफल संघ ने उनके असामयिक निधन की आधिकारिक पुष्टि की है। उनके जाने से भारतीय खेल जगत, विशेषकर शूटिंग बिरादरी में गहरे शोक की लहर दौड़ गई है और इसे खेल इतिहास के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।राणा के कोचिंग करियर का स्वर्णिम अध्याय देश की स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ जुड़ा रहा। उन्होंने मनु के करियर के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौर में उनके खेल को एक नया आयाम दिया। उनके कुशल मार्गदर्शन और गहन प्रशिक्षण का ही परिणाम था कि मनु भाकर ने वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में दो ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया।जानकारी के अनुसार, जसपाल राणा वर्तमान में भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के हाई-परफॉर्मेंस कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पिछले हफ्ते म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित हुए आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भाग लेकर जब भारतीय दल स्वदेश लौट रहा था, तब उड़ान के दौरान विमान में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद उन्हें साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी आवश्यक चिकित्सा प्रक्रियाएं पूरी की गईं और चिकित्सकों की देखरेख में उनका सघन उपचार चल रहा था। दुर्भाग्यवश, उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

जसपाल राणा का जाना भारतीय निशानेबाजी के लिए एक युग का अंत माना जा रहा है। उन्होंने तीन दशकों से भी अधिक समय तक एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और मार्गदर्शक के रूप में इस खेल की सेवा की। 1990 के दशक में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय निशानेबाजी का परचम लहराने वाले राणा देश के सबसे सफल पिस्टल शूटरों में से एक थे। उन्होंने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में अनेक स्वर्ण और रजत पदक जीतकर वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा कायम किया था। उनकी इन बेमिसाल जीतों ने भारत में निशानेबाजी को एक बेहद लोकप्रिय खेल बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई और देश के लाखों युवाओं को इस खेल से जुड़ने की प्रेरणा दी।

संन्यास लेने के बाद, जसपाल राणा ने देश में नई प्रतिभाओं को गढ़ने का संकल्प लिया और कोचिंग की दुनिया में कदम रखा। अपनी बेजोड़ तकनीकी समझ और अनुशासित कार्यशैली के कारण वे जल्द ही भारतीय शूटिंग के सबसे प्रभावशाली मार्गदर्शकों में शामिल हो गए।

मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली, 12 जून (संजय बंसल) सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायालय के हस्तक्षेप की सीमाएं निर्धारित हैं और इस चरण में अदालत चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसने याचिकाकर्ता की सभी दलीलों पर विचार किया है। याचिका में दावा किया गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने यह कहते हुए नामांकन खारिज कर दिया कि उम्मीदवार ने अधूरा फॉर्म भरा तथा अपने खिलाफ लंबित शिकायत मामले की जानकारी नहीं दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि संबंधित मामले में न तो आरोप तय हुए थे और न ही अदालत ने संज्ञान लिया था, इसलिए ऐसी जानकारी न देने के आधार पर नामांकन रद्द करना मनमाना और अवैध है।सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि आरओ के आदेश के खिलाफ निर्वाचन आयोग का रुख किया गया था। आवेदन देने के साथ आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष भी रखा, लेकिन आयोग ने कोई आदेश पारित नहीं किया।मामले में याचिकाकर्ता की ओर से संविधान के अनुच्छेद 329(बी) तथा पूर्व के न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया।

श्रीअकाल तख्त साहिब में बेअदबी करने की कोशिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर 12 जून (निस) श्री दरबार साहिब परिसर में स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी में एक व्यक्ति द्वारा बेअदबी करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की शिकायत पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसीपी (सेंट्रल) सुरिंदर सिंह ने बताया कि 11 जून को एक युवक श्री अकाल तख्त साहिब के पीछे स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी में दाखिल हुआ। इस दौरान उसने वहां स्थापित श्री साहिब को उठाने की कोशिश की। हालांकि, मौके पर मौजूद सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता के चलते उसकी हरकत को तुरंत विफल कर दिया गया और उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी पहचान बाबा अजीत सिंह के रूप में हुई है।एसीपी सुरिंदर सिंह ने कहा कि आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा, ताकि उससे गहन पूछताछ की जा सके। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि उसकी इस हरकत के पीछे क्या मंशा थी और क्या वह किसी अन्य व्यक्ति या समूह के संपर्क में था। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

अगले साल पूर्वोत्तर से हट सकता है अफस्पा: केन्द्र सरकार बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में

नई दिल्ली 12 जून (निस): केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जो क्षेत्र में शांति और विकास की नई दिशा देंगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 तक एक-दो राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) हटाया जाएगा। इसके साथ ही, केंद्र सरकार, असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद वाले क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़ा तेल और गैस उत्पादन फिर से शुरू करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने इस निर्णय के पीछे पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में आए उल्लेखनीय सुधार और उग्रवादी गतिविधियों में आई कमी को प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न शांति समझौतों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति की बहाली संभव हुई है। अफस्पा के दायरे में लगातार की जा रही कटौती इसी प्रगति का प्रमाण है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी दूसरी बड़ी घोषणा कर शाह ने बताया कि केंद्र सरकार तथा असम और नागालैंड की सरकारों के बीच सीमा विवाद वाले उस क्षेत्र में तेल और गैस उत्पादन फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है, जो लंबे समय से विवाद और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण निष्क्रिय पड़ा हुआ था। केंद्र सरकार का अनुमान है कि इस क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के तेल और गैस भंडार मौजूद हैं। उत्पादन शुरू होने के बाद, क्षेत्र की तेल उत्पादन क्षमता वर्तमान 1,000-1,500 बैरल प्रतिदिन से बढ़कर करीब दस गुना तक पहुंच सकती है। इस परियोजना से न केवल देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार का मानना है कि शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के ये कदम पूर्वोत्तर भारत को देश की विकास यात्रा में एक अधिक प्रभावी और गतिशील भूमिका निभाने में सक्षम बनाएंगे।

इंगलैंड में पंजाबी युवक की तेजधार हथियार से हत्या, गांव में पसरा मातम

तरनतारन 12 जून (निस) पंजाब के तरनतारन जिले के खेमकरण के निकटवर्ती सीमावर्ती गांव महिंदीपुर के एक युवक की इंग्लैंड में हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी बीती रात वहां रह रहे अन्य पंजाबी युवकों ने मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार, 26 वर्षीय गुरभेज सिंह, जो अपनी तीन बहनों का इकलौता भाई था, करीब चार साल पहले रोज़गार के लिए इंग्लैंड गया था। वह वहां अपने गांव और अन्य पंजाबी युवकों के साथ काम करता था। बताया जा रहा है कि बीते बुधवार इंग्लैंड के साउथहॉल शहर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने तेजधार हथियार से हमला कर गुरभेज सिंह की हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। सूचना के मुताबिक, साउथहॉल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं, मृतक का शव स्थानीय अस्पताल में रखा गया है।

देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत....

पीएम मोदी 2029 में भी देश के प्रधान सेवक के रुप में काम करेंगे-सीएम सैनी का दावा

चंडीगढ़,12 जून (के.के.संधू) हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 55 साल देश में राज करने वाली राजनीतिक पार्टी ने देश को जो मजबूत करना था वो नहीं किया। कांग्रेस ने देश को केवल और केवल भ्रमित करने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस के झूठ बोलने का काल खंड अब जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है, उनके नेतृत्व में 12वर्षों के सेवा सुशासन से देश तेजी से बदला है। ग्रामीण परिवेश बदला है, शहर बदले है और देश का विकास हुआ है। पीएम मोदी 2029 में भी देश में प्रधान सेवक के रूप में चौथी बार काम करेंगे।मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंचकूला स्थित पंचकमल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 12वर्षीय कार्यकाल पूरे होने पर प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, मेयर श्री श्याम लाल बंसल, बीजेपी उपाध्यक्ष श्रीमती बन्तो कटारिया, जिला प्रभारी श्री रवि बतान, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहाकार श्री राजीव जेटली, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रे भी मौजूद थेपत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों ने भारत को बदलते देखा है। हर प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल दुनियां में भारत की एक नई पहचान लेकर आने वाला कार्यकाल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अपनी ओर से तथा हरियाणा की पौने तीन करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व को नमन किया। जिसने पिछले 12 वर्षों में भारत को विश्व की बड़ी शक्तियों में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत की आवाज जी-20, ब्रिक्स, एससीओ और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर प्रभावी रूप से सुनी जाती है तथा देश निर्णायक भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और धारा 35-ए को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के राष्ट्रीय स्वप्न को साकार किया गया। मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान दुनिया ने भारत की स्वदेशी तकनीक और हथियारों की शक्ति देखी, जबकि 'ऑपरेशन महादेव' के माध्यम से पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा दी गई।उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कठोर और प्रभावी निर्णयों के कारण देश को नक्सलमुक्त बनाने का सपना साकार होने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है तथा आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में **शेष अंतिम पृष्ठ पर**

अहमदाबाद एयर इंडिया त्रासदी- पहली बरसी पर आ सकती है जांच रिपोर्ट, 260 की मौत

अहमदाबाद, 12 जून (निस) अहमदाबाद में हुए भयावह एयर इंडिया विमान हादसे को 12 जून एक साल पूरा हो जाएगा। इस दर्दनाक हादसे की पहली बरसी पर, जांच रिपोर्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) अहमदाबाद में हुए एआई 171 क्रैश की या अंतरिम या फिर फाइनल रिपोर्ट जारी हो सकती है। इस हादसे में 260 लोगों की जान गई थी, और यह रिपोर्ट त्रासदी के कारणों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के एनेक्स 13 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी विमान दुर्घटना की अंतिम रिपोर्ट 12 महीनों के भीतर सार्वजनिक नहीं होती है, तब संबंधित देश को हर बरसी पर जांच की प्रगति का विवरण देने वाला बयान जारी करना अनिवार्य है। इसी प्रोटोकॉल के तहत यह रिपोर्ट सामने आने की संभावना है, जिससे हादसे के पीछे की गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिलेगी ।

गुजरात, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान से सभी भाजपा एवं एक जगह कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध जीते

गांधीनगर 12 जून (निस)राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया-2026 के तहत गुजरात राज्य की चार सीटों के लिए चुनाव परिणामों की आज आधिकारिक घोषणा कर दी गई। गुजरात विधानसभा के सचिव एवं निर्वाचन अधिकारी चेतन पंड्या ने चारों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जून 2026 को गुजरात की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 जून 2026 तक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। इस अवधि के दौरान कुल चार उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए थे। 9 जून 2026 को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की गई, जिसमें सभी चार उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। इसके बाद 11 जून को नामांकन वापस लेने की निर्धारित समयसीमा समाप्त होने तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया।चूंकि चार सीटों के लिए केवल चार ही उम्मीदवार मैदान में थे, इसलिए मतदान की आवश्यकता नहीं रही और चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया। निर्वाचन अधिकारी चेतन पंड्या ने सभी चार उम्मीदवारों को आधिकारिक रूप से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए उम्मीदवारों में जितेंद्र कणजारिया, मानसिंह परमार, राजेश शुक्ल और मुकेश राठवा शामिल हैं।ये नवनिर्वाचित सदस्य राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों राम मोकरिया, नरहरी अमीन, रमीला बारा और शक्तिसिंह गोहिल का स्थान लेंगे। इन चारों मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। इन चार सदस्यों में राम मोकरिया, नरहरी अमीन और रमीला बारा भाजपा से तथा शक्तिसिंह गोहिल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं7

गुजरात से राज्यसभा की चारों सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन होने से राजनीतिक हलकों में चर्चा का माहौल है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई तथा मतदान की आवश्यकता न पड़ने से निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित समय से पहले ही पूर्ण हो गई।इससे पहले मिली खबर के अनुसार 18 जून 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद कई राज्यों में उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की स्थिति स्पष्ट हो गई है। जहां कुछ राज्यों में सभी सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों के बराबर रही, वहीं अन्य राज्यों में चुनावी प्रक्रिया अभी जारी है।

राजस्थान में राज्यसभा की तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी गई है।

नटराजन मामला: कांग्रेस का दिल्ली में जोरदार रोष प्रदर्शन, अब सीट चोरी का आरोप लगाया

नई दिल्ली, 12 जून (निस) नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली में जुटे मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अनेक विधायकों ने भाजपा पर वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी का आरोप लगाया।कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने घटना को देश के इतिहास में पहली बार हुई सीट चोरी बताया। उन्होंने कहा कि आजकल जहाँ वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी की चर्चा थी, वहीं अब भाजपा ने चुनाव से पहले ही सीट चोरी कर ली है। कांग्रेस नेता सिंह ने आरोप लगाया कि जब नटराजन ने अपना नामांकन जमा किया था, तब भी भाजपा कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने और सौदा करने का पूरा प्रयास कर रही थी। उन्होंने 2020 के ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रकरण का जिक्र कर कहा कि वर्तमान विधायकों को भाजपा के साथ सौदा करने का मतलब आत्महत्या करना बखूबी एहसास था। विधायकों के एकजुट खड़े रहने के बाद भाजपा पर बेबुनियाद तरीके से नोटिस ढूंढ़कर नामांकन रद्द कराने का आरोप लगाया गया। जयवर्धन सिंह ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसार, गैर-संज्ञेय अपराध के नोटिस का नामांकन में उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, केवल एफआईआर या न्यायिक **शेष अंतिम पृष्ठ पर**

ममता बैनर्जी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज

कोलकाता 12 जून (निस) पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और समाज में अशांति फैलाने वाले भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। यह शिकायत एक कारोबारी ने की थी, जिसे बाद में एफआईआर में बदल दिया गया। दरअसल मामला 9 मार्च 2026 को आयोजित धर्म मंच कार्यक्रम से जुड़ा है। शिकायतकर्ता तुषार कांति दास के अनुसार, कार्यक्रम में ममता बनर्जी द्वारा दिया गया भाषण भड़काऊ था, जिससे जनता में डर और अशांति फैल सकती थी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था, और राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो सकती थी। आपराधिक धमकी देने का आरोप भी शामिल है। यह एफआईआर 7 जून 2026 को दोपहर 3 बजकर 45 मिनट पर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज की गई है।

सम्पादकीय

मानसून सत्र और भारतीय राजनीति का समुद्र मंथन

जुलाई माह में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट देखने को मिल सकती है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। पिछले सत्र में परिसीमन बिल सरकार संसद में पास नहीं करा पाई थी। बीते महीनों में जिस तरह से सरकार को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, विदेशी निवेशक शेयर बाजार से निवेश किया धन वापस निकाल रहे हैं। कच्चे तेल के आयात से सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार मानसून सत्र में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। देश में खाद्य पदार्थों, ईंधन और घरेलू जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों को लेकर जनता के बड़े वर्ग में नाराजगी दिखाई दे रही है। किसान संगठन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), फसल खरीद और कृषि लागत जैसे मुद्दों पर आंदोलित हैं। वहीं नीट पेपर लीक से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र संगठनों की ओर से सड़क पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। काकरोच के नाम पर युवा जेन-जी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी दलों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सरकार के दबाब में काम करने के आरोप हैं। जबकि सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। सरकार अपने कार्यकाल में हुए विकासकार्यों, कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक उपलब्धियों को सामने रखती है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती बयानबाजी ने संसद के आगामी सत्र को और महत्वपूर्ण बना दिया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही संसद सत्र के पहले अपने-अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस बार विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद का मानसून सत्र आने वाले विधानसभा चुनावों और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में यह मानसून सत्र सरकार के लिए संकटभरा हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को यदि समुद्र मंथन की उपमा दी जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। समुद्र मंथन में जिस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के साथ-साथ सहयोग भी था, उसी प्रकार भारतीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पौराणिक कथा में पहले विष निकला और अंत में अमृत प्राप्त हुआ था। लोकतंत्र के इस राजनीतिक मंथन से मानसून सत्र में कौन लाभान्वित होगा और किसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मानसून सत्र केवल विधायी कार्यवाही का मंच नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकार की नीतियों, विपक्ष की रणनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर व्यापक राजनीतिक बहस का केंद्र बनने जा रहा है। इस राजनीतिक समुद्र मंथन का परिणाम क्या होगा, इसका निर्णय अंततः जनता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ही तय करेंगी। जिस तरह से सत्ता पक्ष ने लोकसभा एवं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों इसके बाद टीएमसी के सांसदों को पार्टी से अलग होकर अलग गुट बनाने या सांसदों से इस्तीफा दिलवाकर विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत है, मानसून सत्र में सरकार कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। इसके लिए सरकार किसी भी स्तर पर अपने आपको सुरक्षित करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। इसका एक संदेश यह भी है, सरकार अंदर से कमजोर है। भाजपा के अंदर से भी असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने चारों ओर से सुरक्षित रहने के लिए घेराबंदी शुरु कर दी है।

प्रजा का खजाना

फारस के शासक साइरस अपनी प्रजा की भलाई में जुटे रहते थे। लेकिन खुद उनका जीवन सादगी से भरा था। वह रियासत की सारी आमदनी व्यापार, उद्योग और खेतीबाड़ी में लगा देते थे। इस कारण शाही खजाना हल्का रहता था। लेकिन प्रजा खुशहाल थी। एक दिन साइरस के दोस्त और पड़ोसी शासक प्रोशियस उनके यहां आए। उनका मिजाज साइरस से बिल्कुल अलग था। उन्हें प्रजा से ज्यादा अपनी खुशहाली की चिंता रहती थी। उनका खजाना हमेशा भरा रहता था। बातों-बातों में जब प्रोशियस को साइरस के खजाने का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने साइरस से कहा, अगर आप इसी तरह प्रजा के लिए खजाना लुटाते रहोगे तो एक दिन वह एकदम खाली हो जाएगा। आप कंगाल हो जाओगे। अगर आप भी मेरी तरह खजाना भरने लगें तो आपकी गिनती मेरी तरह सबसे धनी शासकों में होने लगेगी। साइरस मुस्कराए फिर बोले आप दो दिन ठहरिए मैं इस मामले में लोगों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। उन्होंने घोषणा करवा दी कि एक बहुत बड़े काम के लिए साइरस को दौलत की निहायत जरूरत है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रजा मदद करेगी। दो दिन पूरा होने से पहले ही शाही महल के बाहर मोहरों, सिक्कों व जेवरों का बड़ा ढेर लग गया। यह देख प्रोशियस हैरत में पड़ गए। साइरस ने कहा, मैंने रियासत का खजाना लोगों की खुशहाली पर खर्च करके एक तरह से उन्हीं को सौंप दिया है। लोग उसमें इजाफा करते रहते हैं। मुझे जब जरूरत होगी वे मुझे लौटा देंगे जबकि तुम्हारा खजाना बांझ है, वह कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा है।

बचपन को श्रम नहीं, शिक्षा सुरक्षा एवं सम्मान का अधिकार मिले

- ललित गर्ग

हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानवता के अंत:करण को झकझोरने वाला अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं होता। उसके हाथों में औजार, ईंट, बर्तन, हथौड़े, कूड़े की बोरी या कारखानों की मशीनें नहीं, बल्कि किताबें, खिलौने, रंग, सुनहले सपने और संभावनाएं होनी चाहिए। बचपन जीवन का वह स्वर्णिम काल है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, संस्कार, शिक्षा और भविष्य की नींव रखी जाती है। यदि यही काल श्रम, शोषण और अभाव की भट्टी में झोंक दिया जाए तो केवल एक बच्चे का नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन-आईअलओ द्वारा 2002 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की भयावहता के प्रति वैश्विक चेतना जगाना और इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को गति देना है। वर्ष 2026 में भी यह दिवस ऐसे समय पर आ रहा है जब दुनिया तकनीकी विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक प्रगति के नए आयाम छू रही है, लेकिन दूसरी ओर करोड़ों बच्चे आज भी शिक्षा और बचपन के अधिकार से वंचित हैं। यह विडम्बना मानव सभ्यता के सामने एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। जब हम किसी ढाबे, होटल, चाय की दुकान, कारखाने, गैरेज, ईंट-भट्टे, खेत या ट्रैफिक सिग्नल पर किसी मासूम बच्चे को कठिन श्रम करते देखते हैं, तब अक्सर हमारी संवेदना कुछ क्षणों के लिए जागती है और फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कब तक हम इस पीड़ा को सामान्य मानते रहेंगे? क्या हम उस बचपन की चीख नहीं सुन पा रहे जो अपने अधिकारों से वंचित होकर मजदूरी के अंधेरे में खो रहा है?

आज भी विश्व में करोड़ों बच्चे किसी न किसी रूप में बाल श्रम में संलग्न हैं। इनमें से बड़ी संख्या खतरनाक परिस्थितियों में काम करती है, जहां उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बाधित होता है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, विस्थापन, तस्करी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं बाल श्रम की प्रमुख वजहें हैं। परिवार की आर्थिक विवशताएं बच्चों को स्कूल की बजाय काम की दुनिया में धकेल

देती हैं। लेकिन गरीबी का समाधान बच्चों से काम कराना नहीं, बल्कि परिवारों को सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं है; यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, आत्मविश्वास और भविष्य छीन लेता है। जो बच्चा विद्यालय में होना चाहिए, वह यदि कारखाने में है, तो यह केवल उस बच्चे की नहीं, पूरे समाज की विफलता है। बाल श्रम गरीबी का चक्र भी बनाए रखता है, क्योंकि अशिक्षित बच्चा बड़ा होकर कम आय वाले कार्यों तक सीमित रह जाता है और अगली पीढ़ी भी उसी अभाव में जीने को मजबूर होती है।

भारत सहित अनेक देशों में बाल श्रम रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईअलओ के कन्वेंशन 138 और कन्वेंशन 182 न्यूनतम कार्य आयु और बाल श्रम के सबसे खतरनाक रूपों पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। भारत में भी बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार कानून मौजूद हैं। लेकिन कानूनों की प्रभावशीलता उनके कठोर और ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कई बार कानूनी प्रावधान होने के बावजूद बाल श्रम छिपे हुए रूपों में जारी रहता है। आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने की है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जन-जागरण अभियान चलाए जाने चाहिए। विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, मीडिया, उद्योग जगत और नागरिक समाज को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और महिला अधिकारों को लेकर वैश्विक चेतना विकसित हुई है, उसी प्रकार बाल अधिकारों के लिए भी विश्वव्यापी जनमत तैयार करना होगा। कैसा विरोधाभास है कि हमारा समाज, सरकार और राजनीतिज्ञ बच्चों को देश का भविष्य मानते नहीं थकते लेकिन क्या इस उम्र के लगभग 25 से 30 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी के जरिए उनका बचपन और उनसे पढने का अधिकार छीनने का यह सुनियोजित षड्यंत्र नहीं लगता? मिसाल के तौर पर एक कानून बनाकर हमने बच्चों से उनका बचपन छिनने की कुचेष्टा की है। इस कानून में हमने यदि पारिवारिक कामधंधा या रोजगार है तो 4 से 14 की उम्र के बच्चों से कानूनन काम कराया जा सकता है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कैसी विडम्बना है कि जब इस उम्र के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, खानदानी व्यवसाय के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को शिक्षा, खेलकूद और सामान्य बाल्य सुलभ व्यवहार से वंचित किया जा रहा है और हम अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर हकीकत में हम उन्हें पैसा कमाकर लाने की मशीन बनाकर अंधकार में धकेल रहे हैं। विशेष रूप से डिजिटल युग में तकनीक का उपयोग बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शी निगरानी, बाल श्रम शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, त्वरित कार्रवाई तंत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला में कहीं भी बाल श्रम का उपयोग न हो। जो कंपनियां ऐसा करती पाई जाएं, उनके विरुद्ध कठोर आर्थिक और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाल श्रम समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा है। केवल विद्यालय खोल देना पर्याप्त नहीं है; शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आकर्षित करे, जीवनोपयोगी कौशल दे और उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करे। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है। हमें यह भी समझना होगा कि बचपन केवल जीवित रहने का नाम नहीं है; बचपन का अर्थ है सपने देखने की स्वतंत्रता, खेलने का अधिकार, सीखने का अवसर, स्नेहपूर्ण वातावरण और सुरक्षित भविष्य।

टीएमसी में आखिर असंतोष क्यों पनपा, गहरी साजिश की आशंका

- सौरभ वार्ष्णेय

पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अजेय दिखाई देने वाली ममत बेनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी आज गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष, बगावत और नेतृत्व को लेकर सवाल लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।अगर मंथन करेंगे तो सर्व प्रथम सत्ता-विरोधी माहौल का असर दिखाई दे रहा है। लगभग 15 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहने के बाद टीएमसी को स्वाभाविक रूप से सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार, स्थानीय स्तर पर कथित कट मनी संस्कृति, प्रशासनिक अक्षमता और कुछ चर्चित घोटालों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचाया। कई विश्लेषकों का मानना है कि जनता के एक वर्ग में बदलाव की इच्छा मजबूत हो गई थी नेतृत्व और उत्तराधिकार की चुनौती = टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा ममता बनर्जी का व्यक्तिगत जनाधार रहा है। लेकिन समय के साथ पार्टी में नेतृत्व का अत्यधिक केंद्रीकरण दिखाई देने लगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बेनर्जी की भूमिका को लेकर भी संगठन के भीतर मतभेद सामने आए हैं। हाल के घटनाक्रमों में कई नेताओं और सांसदों द्वारा असंतोष व्यक्त किए जाने की खबरें आई हैं।बगावत ने संकट को गहरा किया = सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बड़ी संख्या में विधायकों ने बागी रुख अपनाया। रिपोर्टों के अनुसार 58 से अधिक विधायकों ने अलग समूह का समर्थन किया और पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती दी। इससे ञ्जरूष्ट की एकजुटता पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं।संगठनात्मक कमजोरी उजागरः चुनावी हार के बाद कई स्थानीय इकाइयों और समितियों को भंग करने की नौबत आई। यह कदम आत्ममंथन के लिए उठाया गया बताया गया, लेकिन इससे यह भी संकेत मिला कि पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा दबाव में है।कानूनी और विवादास्पद मामलों का दबाव = पार्टी के कुछ नेताओं पर लगे

आरोप, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और हस्ताक्षर जालसाजी जैसे विवादों ने भी ञ्जरूष्ट की मुश्किलें बढ़ाई हैं। विपक्षइन मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पार्टी को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। आगे की राह ?टीएमसी का संकट केवल चुनावी हार का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व संबंधी प्रश्नों और लंबे समय तक सत्ता में रहने से पैदा हुई चुनौतियों का संयुक्त परिणाम है। फिर भी ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की सबसे संघर्षशील नेताओं में गिनी जाती हैं। यदि वे संगठन को पुनर्गठित करने, असंतुष्ट नेताओं को साथ लाने और जनता के बीच विश्वास बहाल करने में सफल रहती हैं, तो टीएमसी फिर से मजबूत वापसी कर सकती है। लेकिन यदि आंतरिक कलह और नेतृत्व विवाद जारी रहे, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ञ्जरूष्ट का प्रभाव पहले जैसा बनाए रखना कठिन हो सकता है। वर्तमान संकट पार्टी के लिए आत्ममंथन का अवसर भी है और अस्तित्व की चुनौती भी।

टीएमसी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों में बिखराव क्यों ?

हाल के दिनों में राज्यसभा सांसद सुखेंदु सेखर रॉय के इस्तीफे और कई सांसदों के असंतोष की खबरों ने यह संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर असहमति अब खुलकर सामने आ रही है।टीएमसी के राज्यसभा सदस्यों में बढ़ते बिखराव के पीछे कई कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण नेतृत्व को लेकर असंतोष है। पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सीमित दायरे में सिमट गई है और वरिष्ठ नेताओं की राय को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद यह असंतोष और बढ़ गया है।दूसरा कारण राजनीतिक भविष्य की चिंता है। सत्ता से बाहर होने के बाद अनेक सांसद और विधायक अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं। ऐसे समय में कुछ नेताओं द्वारा नए राजनीतिक विकल्प तलाशना स्वाभाविक माना जा रहा है। मीडिया में कई सांसदों के संभावित अलग रुख अपनाने की चर्चा भी सामने आई है।तीसरा कारण भ्रष्टाचार और संगठनात्मक कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे प्रश्न हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पार्टी में बढ़ती गुटबाजी, भ्रष्टाचार और जनभावनाओं से दूरी की बात कही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संकट केवल चुनावी हार का नहीं बल्कि संगठनात्मक विश्वास के क्षरण का भी है।चौथा कारण टीएमसी के भीतर उभरता शक्ति-संघर्ष है। पार्टी के पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने की चुनौती लगातार बढ़ती गई है। चुनावी पराजय के बाद यह संघर्ष अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा है।राज्यसभा सदस्यों में यह बिखराव केवल टीएमसी की समस्या नहीं है, बल्कि यह उन सभी क्षेत्रीय दलों के लिए चेतावनी है जो किसी एक नेता के करिश्मे पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। जब संगठनात्मक लोकतंत्र कमजोर होता है और संवाद की गुंजाइश घटती है, तब असंतोष विद्रोह का रूप ले लेता है। टीएमसी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं का विश्वास पुनः अर्जित करने की है। यदि पार्टी नेतृत्व समय रहते संवाद, संगठनात्मक सुधार और सामूहिक नेतृत्व की दिशा में कदम नहीं उठाता, तो राज्यसभा में दिखाई दे रहा यह बिखराव भविष्य में और गहरा राजनीतिक संकट बन सकता है।

जनविश्वास, विकास एवं इतिहास के आईने में मोदी शासन

विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला'

10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले नेता बन गए। 4,399 दिनों के कार्यकाल के साथ उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से इस उपलब्धि को भारतीय राजनीति की एक बड़ी घटना माना जा रहा है।किंतु लोकतंत्र में केवल रिकॉर्ड ही इतिहास नहीं बनाते, बल्कि इतिहास इस बात का भी मूल्यांकन करता है कि किसी नेता ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया और राष्ट्र की दिशा को किस हद तक प्रभावित किया।यहीं से मोदी युग के मूल्यांकन की वास्तविक शुरुआत होती है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन भारतीय लोकतंत्र की संभावनाओं का प्रतीक है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना और लगातार तीन बार जनादेश प्राप्त करना स्वयं में असाधारण उपलब्धि है। वर्ष 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब देश भ्रष्टाचार, नीतिगत गतिरोध, आर्थिक सुस्ती और प्रशासनिक अक्षमता के आरोपों से घिरा हुआ था। जनता परिवर्तन चाहती थी और मोदी उस परिवर्तन के प्रतीक बनकर उभरे।पिछले बारह वर्षों में सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार किया।प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्ज्वला योजना, जनधन खाते,आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन,स्वच्छ भारत अभियान और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाई।प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाई और बिचौलियों की भूमिका कम करने का प्रयास किया।ग्रामीण भारत में बिजली,सड़क,शौचालय और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ। करोड़ों परिवार पहली बार औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से

जुड़े। सरकार के समर्थक इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का नया मॉडल बताते हैं।डिजिटल इंडिया अभियान ने शासन की कार्यशैली बदल दी। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हुआ। यूपीआई ने वित्तीय लेन-देन को सरल बनाया और तकनीक आधारित सेवाओं का विस्तार हुआ। स्टार्टअप इंडिया और नवाचार को प्रोत्साहन मिलने से भारत विश्व के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में गिना जाने लगा।विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं।चंद्रयान-3 की सफलता और अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक पहचान दिलाई।जी-20 की अध्यक्षता और वैश्विक मंचों पर बढ़ती सक्रियता ने भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया।राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार की नीतियों को व्यापक समर्थन मिला।सीमापार आतंकवाद के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदमों ने सरकार की निर्णायक छवि को मजबूत किया।अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक कानून और जीएसटी जैसे निर्णयों ने राजनीतिक विमर्श को नई दिशा दी। किसी भी लोकतंत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन केवल सरकारी दावों या समर्थकों की प्रशंसा से नहीं किया जा सकता। एक स्वतंत्र टिप्पणीकार की जिम्मेदारी उपलब्धियों के साथ-साथ चुनौतियों और प्रश्नों को भी सामने रखना है।भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन आम नागरिक का अनुभव केवल जीडीपी वृद्धि दर से तय नहीं होता। महँगाई,रोजगार, आय और जीवन स्तर उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं।पिछले वर्षों में बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बनी रही है।लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, लेकिन अवसर सीमित दिखाई देते हैं।भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं में असंतोष भी पैदा किया है। विकसित भारत का सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार में परिवर्तित नहीं होता।मुद्रा योजना और स्वरोजगार आधारित पहलों को सरकार अपनी सफलता बताती है,किंतु अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग यह प्रश्न भी उठाता है कि इन योजनाओं से उत्पन्न रोजगार कितने स्थायी और टिकाऊ हैं।इसी प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के बावजूद ऋण वसूली, एनपीए और वित्तीय अनुशासन के प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। कृषि क्षेत्र में भी तस्वीर मिश्रित दिखाई देती है।किसान सम्मान निधि,सिंचाई योजनाओं और तकनीकी सुधारों ने सकारात्मक प्रभाव डाला है,लेकिन खेती की लागत, प्राकृतिक जोखिम और आय की अनिश्चितता आज भी किसानों की बड़ी चिंता है। कृषि कानूनों के विरुद्ध हुआ लंबा किसान आंदोलन इस बात का संकेत था कि आर्थिक सुधारों के साथ संवाद और सहमति भी उतनी ही आवश्यक है।मोदी युग का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक केंद्रीकरण का है। समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व कहते हैं,जबकि आलोचक संस्थागत संतुलन और लोकतांत्रिक विमर्श के कमजोर होने की आशंका व्यक्त करते हैं। मीडिया,जाँच एजेंसियों और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है।सामाजिक स्तर पर भी देश ने कई परिवर्तन देखे हैं।एक ओर राष्ट्रीय गौरव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विरासत संरक्षण की भावना मजबूत हुई है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक ध्रुवीकरण और वैचारिक विभाजन को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जाती रही हैं।

यूपी के मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकने को स्पेशल सेल का गठन, राज्यपाल का निर्देश

लखनऊ 12 जून (निस) उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अब धार्मिक धर्मांतरण से संबंधित मामलों की रोकथाम और निगरानी के लिए विशेष प्रकोष्ठ (सेल) का गठन होगा। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) से जुड़े कथित धर्मांतरण प्रकरणों को गंभीरता से लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। इस पहल को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसने अपने सभी संबद्ध कॉलेजों को इस बारे में आदेश दे दिया हैं। कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर एम.बोबड़े के पत्र और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अमित देवगन के निर्देशों के बाद, सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों से जल्द से जल्द इन विशेष सेलों का गठन कर उसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह सेल छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखेगा। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में एक सुरक्षित, स्वस्थ और भयमुक्त वातावरण बनाए रखना है। किसी भी शिकायत या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कॉलेजों को जागरूकता अभियान चलाने और संबंधित नियमों, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्यपाल के इस सख्त निर्देश के बाद, प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करने की कवायद तेजी से शुरू हो गई है, ताकि इसतरह संवेदनशील मुद्दों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।

हौजरानी अग्निकांड के बाद दिल्ली की सोसाइटियों में सुरक्षा ऑडिट की तेज हुई मांग, डर के साये में हैं लोग

नई दिल्ली 12 जून (निस) हौजरानी के अवैध होटल में अग्निकांड के बाद राजधानी की विभिन्न सोसाइटियों में सुरक्षा को लेकर आरडब्ल्यूए की चिंता बढ़ गई है। सोसाइटियों में अवैध निर्माण, अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और सार्वजनिक स्थानों पर संचालित हो रहे असुरक्षित फूड स्टालों को लेकर कई आरडब्ल्यूए ने संबंधित विभागों को शिकायतें भेजी हैं। आरडब्ल्यूए की तरफ से अब सोसाइटियों में फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल सेफ्टी जांच और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग अधिक गंभीरता से उठाई जाने लगी है। न्यू फ्रेंड्स कालोनी व कई अन्य सोसाइटियों में एसी में आग लगने की घटनाओं के बाद एहतियातन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करने का फैसला लिया गया है। सफदरजंग एन्क्लेव आरडब्ल्यूए ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली सरकार से क्षेत्र में स्थित इमारतों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों का नियमित फायर ऑडिट और स्ट्रक्चरल सेफ्टी आडिट कराने मांग की है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पंकज अग्रवाल का कहना है कि वे पहले भी कई बार इस मांग को उठा चुके हैं। इलाके में अवैध निर्माण, अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संचालित असुरक्षित प्रतिष्ठान बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं।

दिल्ली में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की नई रणनीति

नई दिल्ली 12 जून (निस)सैदुलाजाब में पिछले दिनों अवैध इमारत गिरने से छह लोगों की मौत और फिर हौजरानी के एक होटल में आग लगने से 22 जानें जाने के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद टूट गई है। इन दर्दनाक हादसों से पुलिस अधिकारियों के कान पर जूं रेंगी है, जिसके बाद अब एक नई और सख्त रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत किसी भी क्षेत्र में अवैध निर्माण होने पर अब सीधे बीट अफसरों पर भी गाज गिरेगी। दोनों हादसों से सबक लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने बीट अफसरों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीट अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करें और नजर रखें कि कहां अवैध निर्माण हो रहा है। वे संबंधित मकान मालिक से पूछेंगे कि उनके पास निर्माण के लिए नगर निगम की अनुमति है या नहीं। इसके बाद निर्माण की लिखित सूचना निगम को दी जाएगी। यदि निगम के अधिकारी इस सूचना पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो बीट अफसर सीधे अपने जिले के पुलिस उपायुक्त को सूचित करेंगे, जिसके बाद उपायुक्त खुद कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। बीट अफसर ही पुलिसिंग की पहली सीढ़ी होते हैं, जो क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। छह जून को डीसीपी से निर्देश मिलने के बाद सभी बीट अफसर अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं और अवैध निर्माणों की लिखित शिकायतें निगम के पास पहुंचने लगी हैं।

दिल्ली- एनसीआर में कब पहुंचेगा मानसून? आईएमडी ने दिया ताजा अपडेट

नई दिल्ली 12 जून (निस) मौसम के बदले मिजाज के बीच तेज धूप में उमस भरी गर्मी एक बार फिर दिल्लीवासियों का हाल बेहाल कर रही है। हीट इंडेक्स तापमान से कहीं ज्यादा दर्ज हो रहा है, तो बिना एसी के राहत नहीं मिल पा रही। कूलर व पंखे बेअसर से हो गए हैं। मौसम विभाग की मानें तो अभी दो दिन और ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। साफ आसमान और दिन भर खिली रही तेज धूप में सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि, हीट इंडेक्स 43.2 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 60 से 22 प्रतिशत दर्ज किया गया। लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आसमान साफ रहेगा। धूप निकली रहेगी। 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 43 और 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी।

संजय सिंह ने कांग्रेस, पीएम मोदी और विदेश नीति पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली, 12 जून (निस)आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि जब चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के भाजपा के साथ मिले होने की बात सभी को पता है, तब उन्होंने सपोर्टिंग कैंडिडेट का पर्चा क्यों नहीं भरवाया। आप नेता सिंह ने कहा कि इसतरह के समय में जब एक-एक सांसद महत्वपूर्ण है, यह घटना भाजपा को राज्यसभा में आसानी से जीत दिला देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मीनाक्षी का पर्चा गलत ढंग से खारिज हुआ है और चुनाव आयोग भाजपा के हाथ में खेल रहा है। मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे के बाद, संजय सिंह ने ओमान तट पर हुए वाणिज्यिक जहाज पर हमले की घटना पर चिंता व्यक्त की।

एमबीबीएस इंटर्न्स ने खोला मोर्चा, स्टाइपेंड बढ़ाकर 30 हजार करने की मांग

बिलासपुर 12 जून (निस) छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस इंटर्न्स के स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग तेज हो गई है। भारतीय चिकित्सा संघ चिकित्सा छात्र नेटवर्क (आईएमए-एमएसएन) छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत सोमवार को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर के अधिष्ठाता डॉ. रमनेश मूर्ति को ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों ने वर्तमान 15 हजार 900 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड को बढ़ाकर लगभग 30 हजार रुपये करने की मांग की है। आईएमए-एमएसएन छत्तीसगढ़ के सह-अध्यक्ष डॉ. निलय तिवारी एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक व नोडल अधिकारी डॉ. भूपेंद्र कश्यप के मार्गदर्शन में छात्रों ने अधिष्ठाता डॉ. रमनेश मूर्ति को ज्ञापन सौंपा। अभियान को सफल बनाने में विनय कुमार, यशवंत पात्रे, छाया मंडावी, कोमल मित्तल, डॉ. कृति दुबे, प्रमोद साहू, मुस्कान कुमावत और मयंक यादव शामिल रहे। आईएमए-एमएसएन के अनुसार इस अभियान को राज्य के चिकित्सा छात्रों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अब तक विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से 6,468 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो चुकी हैं। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से लेकर इंटर्न्स तक सभी छात्र इस मांग के समर्थन में एकजुट होकर भागीदारी निभा रहे हैं। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अधिष्ठाता डॉ. रमनेश मूर्ति ने छात्रों की मांगों को उचित बताते हुए कहा कि वर्तमान स्टाइपेंड वास्तव में काफी कम है और इसमें वृद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ज्ञापन को आगे की कार्रवाई के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय तथा मंत्रालय तक भेजा जाएगा। आईएमए-एमएसएन ने कहा है कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में ज्ञापन सौंपने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं होने पर व्यापक आंदोलन पर विचार किया जा सकता है।

बच्चों को मिलेगा स्मार्ट और बाल-अनुकूल शिक्षण माहौल

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के तहत बिलासपुर के लिंगियाडीह में विकसित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र जिले की 200 आंगनबाडियों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए संचालित ?4.72 करोड़ की परियोजना का हिस्सा है। लोकार्पण समारोह में एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव होती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को बेहतर सीखने का वातावरण उपलब्ध कराएगा और उनके शारीरिक एवं बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में महाप्रबंधक (सीएसआर) अजय बेहरा सहित सीएसआर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वर्तमान में इस केंद्र में 22 बच्चे नामांकित हैं। शुभारंभ के अवसर पर बच्चों को पुस्तकें, पेंसिल, ड्राइंग पैड, स्केच बुक सहित विभिन्न शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। उन्नत आंगनबाड़ी केंद्र में बाल-अनुकूल शिक्षण कक्ष, आधुनिक फर्नीचर, बेहतर स्वच्छता सुविधाएं और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिससे बच्चों को आकर्षक एवं सुविधाजनक वातावरण में शिक्षा मिल सके। उल्लेखनीय है कि एसईसीएल शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जिले में कई महत्वपूर्ण सीएसआर परियोजनाएं संचालित कर रहा है।

एनसीसी कैडेट्स ने प्रशिक्षण शिविर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिखेरी प्रतिभा की चमक

ग्वालियर 12 जून (निस) 15 एमपी बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित सीएटीसी-38 प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) एवं पूर्व विधायक श्री जयभान सिंह पवैया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

शासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय, डीडी नगर, महाराजपुर में 1 जून से 10 जून तक आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भिंड, डबरा और दतिया जिले के 451 एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैडेट्स ने देशभक्ति गीत, समूह नृत्य तथा अन्य रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि जयभान सिंह पवैया ने कैडेट्स के अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि एनसीसी युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी कैडेट्स के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शिविर का संचालन कर्नल डी.एस. वर्मा के नेतृत्व में किया जा रहा है। शिविर के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव सरिन एवं सूबेदार मेजर जाफर अली ने व्यवस्थाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव सरिन ने थल सैनिक कैंप (टीएससी) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कैडेट्स को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और कठिन परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण शिविर कैडेट्स में अनुशासन, नेतृत्व कौशल, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एक अधिकारी निलंबित, दूसरे को नोटिस-नगर निगम में संपत्तिकर वसूली और बैंक खातों में जमा राशि के मिलान के दौरान सामने आई वित्तीय अनियमितताओं पर निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर एक सहायक राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि तत्कालीन प्रभारी राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।नगर निगम की लेखा शाखा द्वारा ई-नगर पालिका पोर्टल पर दर्ज संपत्तिकर वसूली और बैंक में जमा राशि का मिलान किए जाने पर कुल 16,081 रुपए का अंतर सामने आया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वार्ड क्रमांक 25 और 66 में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक श्री अंकित शर्मा द्वारा वसूली गई नकद राशि और चेकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक में जमा नहीं कराया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार कई चेक लंबे समय तक बैंक में जमा नहीं किए गए और कुछ मामलों में चेक क्लियरेंस की स्थिति भी पोर्टल पर समय पर अपडेट नहीं की गई, जिससे रिकॉर्ड में असंगति बनी रही। इसे गंभीर वित्तीय लापरवाही मानते हुए निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने सहायक राजस्व निरीक्षक श्री अंकित शर्मा को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इसी प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी राजस्व निरीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई है। जांच में यह पाया गया कि अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्राप्त संपत्तिकर राशि और चेकों की समयबद्ध बैंक जमा प्रक्रिया तथा उनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उनके स्तर पर थी, लेकिन इसमें अपेक्षित निगरानी नहीं बरती गई। इस पर निगम प्रशासन ने उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।

भांजे ने मामी से किया दुष्कर्म, पति और ससुराल वालो ने नहीं लिया एक्शन, प्रताड़ित होकर मामी ने आत्महत्या करने खा लिया जहर

भोपाल 12 जून (निस) शहर के देहात थाना इलाके के मिसरोद क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता ने अपने भांजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के साथ ही उसकी हरकतों से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस पीड़िता के बयान दर्ज करने पहुचीं तब ज्यादती की घटना का खुलासा हुआ। पीड़िता का यह भी आरोप है की जब उसने आरोपी की करतूत अपने पति और ससुराल वालो को बताई तब उन्होनें भी आरोपी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया यहॉ तक की उसे फटकार लगाकर समझाइश तक नहीं दी। पुलिस के अनुसार मिसरोद इलाके के एक गांव में अपने पति के साथ रहने वाली 35 वर्षीय विवाहिता अंजना रॉय (परिवर्तित नाम) घरेलू महिला है। उसका पति सब्जी का काम करता है, जिसके चलते वह रोजाना सब्जी खरीदने के लिए मंडीदीप स्थित मंडी जाता है। उसी गांव में पीड़िता के घर के पास ही रहने वाला आरोपी सूनील रिश्ते में उसके पति को दूर का भांजा लगता है। 9 जून को विवाहिता ने अपने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिवार वालो ने उसे इलाज के लिये अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल प्रंबधन में उसे भर्ती कर इलाज शुरु करने के साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर हादसे के कारणो को जानने के लिये पीड़िता के बयान दर्ज करने पुलिस अस्पताल पहुचीं। जहां महिला ने पुलिस को बताया की 5 जून को उसका पति अपने काम पर गया था। पति की गैर मौजूदगी में आरोपी सूनील उसके घर में घुस आया और उसे धमकाते हुए बलपूर्वक उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। इसके बाद आरोपी कई बार इसी तरह की हरकत करता रहा। पीड़िता ने उसकी शिकायत अपने पति और परिजनों से की। आरोप है, कि उसके पति ने भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया यहॉ तक की आरोपी को न तो उसकी हरकत के लिये डांटा और न ही आगे से परेशान करने की समझाइश दी। पीड़िता ने बताया कि पति के इस रवैये के कारण आरोपी की हरकतें लगातार बढ़ती गई। कई शिकायतों के बाद भी परिवार वालो ने आरोपी को कुछ नहीं कहा तब वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई और तंग आकर खुदकुशी करने के लिये जहरीला पदार्थ खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान दिए गए पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

तीन थानो के भारी पुलिस बल ने फिर दी ईरानी डेरे पर दबिश, 17 हजार के ईनामी फरार आरोपी सहित दो बदमाश गिरफ्तार

भोपाल 12 जून (निस) फरार अपराधियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए निशातपुरा पुलिस ने इलाके में स्थित ईरानी डेरा अमन कॉलोनी पर भारी पुलिस बल के साथ एक बार फिर दबिश दी। जानकारी के मुताबिक करीब 40 पुलिसकर्मियों की टीम के साथ कॉलोनी में दी गई दबिश के दौरान इलाके में एक बार फिर अफरा-तफरी फैलने लगी। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 हजार रुपए के इनामी निगरानी बदमाश सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार इनामी बदमाश ने पुलिस को बताया कि वह डेरे में लंबे समय से फरारी काट रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस कमिश्नर संजय सिंह के निर्देश पर 10 जून की शाम ईरानी डेरे में सर्चिंग और रेड कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने संदिग्धों की तलाश के साथ ही फरार आरोपियों और वारंटियों की जानकारी जुटाने के बाद कार्रवाई शुरू की। - **24 वारदातो के आरोपी सालिग उर्फ रेहान को दबोचा - 17 हजार का ईनामी, तीन थानो की पुलिस को थी तलाश** कार्रवाई के दौरान टीम ने निशातपुरा थाने के निगरानी बदमाश सालिग उर्फ रेहान ईरानी पिता शौकत ईरानी (32) निवासी अमन कॉलोनी, ईरानी डेरा को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भोपाल सहित अलग-अलग जिलों में लूट, चोरी, जालसाजी, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे 24 गंभीर अपराध दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी पर अलग-अलग मामलों में 17 हजार का इनाम घोषित था। इसमें थाना रानीपुर जिला बैतूल के प्रकरण में 10 हजार, कोतवाली रायसेन के मामले में 5 हजार और थाना पिपलानी भोपाल के प्रकरण में 2 हजार का इनाम शामिल है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी था। पुलिस ने जिला पन्ना के एक मामले में संदेही रिजवान हुसैन पिता आशिक अली (40) निवासी, अमन कॉलोनी, ईरानी डेरा को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रिजवान के खिलाफ चोरी, लूट, जालसाजी और मारपीट सहित 15 गंभीर अपराध मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों में दर्ज हैं। अफसरो के मुताबिक दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अनुमान है की पूछताछ के दौरान अन्य वारदातों और गिरोह से जुड़े लोगों के संबंध में अहम जानकारी मिल सकती है।

पिछले साल किया था मर्डर लोनी में जमानत पर बाहर आए युवक को चाकू घोंपकर मार डाला

नई दिल्ली 12 जून (निस) दिल्ली एनसीआर के लोनी में 21 साल के लड़के को चार लोगों ने चाकू घोंपकर मार डाला। पिता का आरोप है कि कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने उसे मारा है। मृतक लड़के बीते साल एक युवक की हत्या कर दी थी। वह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर आया था। दिल्ली एनसीआर के लोनी थाना क्षेत्र में बुधवार रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक कुछ समय पहले ही हत्या के मामले में जेल से जमानत पर आया था। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने मामले में चार के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच में जुटी है। लोनी थाना क्षेत्र में अशोक विहार की आशियाना सिटी कॉलोनी में 21 वर्षीय युवक तस्लीम रहता था। पिता असगर ने बताया कि बेटा का घर से कुछ दूरी पर सैलून है।

बिना इजाजत 1.8 करोड़ में दिया था दो एक्स्ट्रा फ्लोर बनाने का ठेका

नई दिल्ली 12 जून (निस) सैदुलाजाब में 30 मई को हुए बिल्डिंग हादसे की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक करमवीर के बाद मंगलवार को ठेकेदारों मनीष खत्री और अवनीश गुप्ता को भी वसंत कुंज स्थित अपने वकील के ऑफिस के पास गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध निर्माण का पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब तीन महीने पहले मनीष और अवनीश को इमारत पर दो एक्स्ट्रा फ्लोर बनाने का ठेका दिया गया था। करीब 1.8 करोड़ में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सूत्रों के मुताबिक मनीष की कंपनी करीब 8 साल पुरानी है और वह सैदुलाजाब, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों में कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा है। पुलिस का दावा है कि वह करमवीर का रिश्तेदार भी है। जांच में यह भी पता चला है कि मनीष पहले भी करमवीर की दो अन्य बिल्डिंग के निर्माण कार्य में शामिल रहा था। वहीं, पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा यह हुआ है कि करीब 8 साल पहले बनी इस बिल्डिंग की संरचना एक्स्ट्रा फ्लोर का भार उठाने के लिए तैयार नहीं थी। बेसमेंट और नींव की क्षमता सीमित थी, लेकिन इसके बावजूद ऊपर निर्माण शुरू कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि 5वीं मंजिल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, जबकि छठी मंजिल पर काम चल रहा था। हालांकि हादसे से कुछ दिन पहले रुपये को लेकर हुए विवाद के कारण निर्माण कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।

कूड़े से बने 148 किमी हाइवे पर दौड़ रहीं गाड़ियां

नई दिल्ली 12 जून (निस) जिस 75 किमी लंबे अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर -2) पर गाड़ियां रफ्तार भर रही हैं, उसके निर्माण में कूड़े के पहाड़ से निकला 10.2 लाख मीट्रिक टन कचरा इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा जो डीएनडी से सोहना तक बना है, उसके निर्माण में भी 3.4 लाख मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए ओखला और गाजीपुर लैंडफिल साइट से कचरा लिया गया था। 39.5 किमी लंबे बहसूमा-बिजनौर हाईवे निर्माण में भी दिल्ली के कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कचरे का इस्तेमाल हाईवे निर्माण में बांध बनाने और कैरिजवे के भीतरी लेयर को 250 एमएम तक बनाने में किया गया है। तीनों हाइवे को मिलाकर कुल 148 किमी लंबे हाइवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 14.4 लाख मीट्रिक टन कूड़े का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में कुछ नए रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की भी प्लानिंग की गई है। जिसमें हाइवे के किनारों पर बांध का निर्माण, हाइवे कैरिजवे के भीतरी लेयर को 250 एमएम तक बनाने में कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सर्विस लेन का निर्माण में भी कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है।

नॉर्थ सेंट्रल और साउथ दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार

नई दिल्ली 12 जून (निस) मई के आखिरी दिनों तक हरियाणा से पानी न मिलने और वजीराबाद रिजर्वायर में भी पानी न होने से दिल्ली में कई दिनों तक पानी की किल्लत रही। अब, स्थिति में थोड़ा सुधार है, लेकिन वजीराबाद रिजर्वायर में अभी भी पानी न होने से नॉर्थ, सेंट्रल और पुरानी दिल्ली के एक बड़े हिस्से में पानी की किल्लत है। हरियाणा और दिल्ली सरकार के आपसी बातचीत के बाद हरियाणा से अब पहले की तुलना में अधिक पानी मिल रहा है, जिससे दिल्ली के बाकी हिस्सों में सप्लाई थोड़ी बेहतर हुई है। जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि हरियाणा से अब 125 क्यूसेक से अधिक पानी मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से 940 एमजीडी से अधिक पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी उत्पादन की स्थिति अभी भी उतनी बेहतर नहीं है। क्योंकि जितना नहरी पानी मिल रहा है, उतना ही पानी उत्पादन हो रहा है। नदी से प्लांट में पानी लाने के लिए जो मास्टर वॉटर ड्रेजिंग मशीन से जो चैनल बनाए गए थे, उससे भी कम पानी आ रहा है। क्योंकि नदी में पानी ही नहीं है। मोटर पंप लगा कर जहां-तहां से पानी एकत्रित कर चैनल से लाया जा रहा है। प्लांट में पानी उत्पादन कम होने से नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बड़ी समस्या है।

हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर हो रही ठगी दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया इंटरस्टेट गिरोह का पर्दाफाश

नई दिल्ली 12 जून (निस) दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन ने एक संगठित अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी ऑनलाइन हेलीकॉप्टर और ट्रैवल बुकिंग वेबसाइटों के जरिए देशभर में लोगों से ठगी कर रहा था। पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह का एक और प्रमुख सदस्य श्रेयांश तिवारी उर्फ शिवम है, जो फर्जी वेबसाइटों को विकसित और संचालित करता था, जिसे बाद में ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेड विज्ञापन चलाकर लोगों को इन फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचाते थे और बुकिंग के नाम पर पैसे वसूलते थे, जिसके बाद रिफंड या अतिरिक्त शुल्क के नाम पर और रकम ली जाती थी। पुलिस के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क म्यूल बैंक खातों और डिजिटल माध्यमों के जरिए पैसे को आगे ट्रांसफर करता था। इस गिरोह से जुड़ी लगभग 30 शिकायतों का पता चला है, जिनमें करीब 10 लाख रुपए की साइबर ठगी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 आईपैड, कई एटीएम/डेबिट कार्ड और महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं, साथ ही 20,328 रुपए की राशि बैंक खाते में फ्रीज कर दी गई है।

प्रकाश चौंक से गौरी शंकर मार्ग पर काटी जा रही अवैध मार्केट, नियमों की उड़ रही धज्जियां

यमुनानगर, 12 जून (दिनेश कुमार) : जगाधरी के प्रकाश चौक से गौरी शंकर मंदिर रोड पर भू-माफिया के हौसले बुलंद हैं। यहां तांबे और पीतल की फैक्ट्री के पास खुलेआम अवैध मार्केट काटी जा रही है। मार्केट में बड़े-बड़े शोरूम काट कर महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मार्केट काटने से पहले संबंधित विभाग से न तो लाइसेंस लिया गया और न ही कोई औपचारिकता पूरी की गई।

एक भी कागज नहीं, फिर भी बिक रहे शोरूम

नियम कहते हैं कि कोई भी व्यावसायिक मार्केट या शोरूम बनाने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नक्शा पास कराना, पार्किंग, फायर सेफ्टी और जल निकासी का प्रबंध करना जरूरी होता है। लेकिन यहां एक भी नियम का पालन नहीं किया गया। न सड़क चौड़ी की गई, न पार्किंग की जगह छोड़ी गई। बिना नक्शा पास कराए

ही निर्माण कर शोरूम बेचे जा रहे हैं।

भोले लोगों को दिखाए जा रहे सपने

स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनाइजर भोले-भाले व्यापारियों को बड़े-बड़े सपने दिखाकर शोरूम बेच रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सारी मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि अवैध मार्केट बनने से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। कल को जब विभाग का पीला पंजा चलेगा तो खरीददारों की पूंजी डूब जाएगी।

मिलीभगत का आरोप

लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग के कुछ अफसरों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण संभव नहीं है। दिनदहाड़े शोरूम बन रहे हैं और विभाग आंखें मूंदे बैठा है।

लोगों ने की कार्रवाई की मांग

लोगों ने डीसी यमुनानगर से मांग की है कि प्रकाश चौक से गौरी शंकर मार्ग पर काटी जा रही इस अवैध मार्केट की तुरंत जांच कराई जाए। दोषी अफसरों और कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई हो। अब देखना यह है कि प्रशासन कब नींद से जागता है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाता है।

सरकार की प्रो-एक्टिव नीति से 41 हजार 853 लोगों की घर बैठे बनी पेंशन : डीसी अपराजिता

कैथल, 12 जून (प्रवेश बहादुर) : डीसी अपराजिता ने कहा कि केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आमजन के कल्याणार्थ अनेकों योजनाएं चलाई लागू की गई। जिनका सीधा लाभ जिले के पात्र लोगों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी आमजन के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं।

इनमें एक है सरकार की प्रो-एक्टिव नीति। जिसकी वजह से वर्ष 2022 से अब तक 41 हजार 853 लोगों की घर बैठे ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनी है। उन्हें न तो योजना के लिए आवेदन करना पड़ा और न ही कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े। वहीं सरकार ने पिछले 12 वर्षों में कई बार पेंशन की राशि को बढ़ाया है। डीसी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी दिशा में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रो-एक्टिव मोड में लागू किया गया है, जिससे पात्र व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। पीपीपी में दर्ज आंकड़ों के आधार पर पात्रता पूरी होने पर विभाग स्वयं कार्रवाई कर लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ता है।

डीसी अपराजिता ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा को 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही दिव्यांगता की श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगजन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

उन्होंने बताया कि जिला समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिले में 2 लाख 47 हजार 941 लाभार्थी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

जिले में 1 लाख 22 हजार 260 वृद्धजन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत प्रतिमाह 3,200 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 48 हजार 745 विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को भी प्रतिमाह 3,200 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार 43 हजार 316 महिलाओं को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2,100 रुपये का लाभ मिल रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमितेंद्र श्योकंद ने बताया कि 15 हजार 189 निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, 9 हजार 930 दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन, 5 हजार 307 विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता तथा 2 हजार 51 महिलाओं को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा 673 मंदबुद्धि बच्चों, 461 कैंसर रोगियों तथा 8 बौना एवं 1 किन्नर लाभार्थी को भी सरकार द्वारा नियमित आर्थिक सहायता दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि एसिड अटैक पीड़ितों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार 8 हजार रुपये से 14 हजार 400 रुपये तक मासिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है।

अब 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले उन परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल किया गया है जिनके बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं, जिन्होंने सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करते हुए 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं या निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित ग्रेड हासिल किए हैं।

एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर और गंभीर कार्डियक कंडीशन से पीड़ित महिला को नई जिंदगी मिली

अमृतसर 12 जून (मधु राजपूत) एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, जो फेफड़ों तक फैल चुका था और गंभीर कार्डियक कंडीशन से पीड़ित 59 साल की महिला को लिवासा हॉस्पिटल, अमृतसर में सफल इलाज के बाद नई जिंदगी मिली। महिला के बाएं ब्रेस्ट में एक गांठ थी। विस्तृत जांच से पता चला कि उसे ॥श्वञ्च2-पॉजिटिव, हार्मोन रिसेप्टर-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, जो फेफड़ों तक फैल चुका था। उसे पहले से कोरोनरी

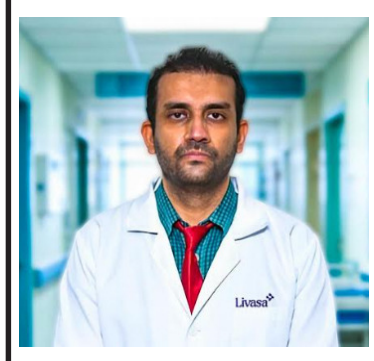

आर्टरी डिजीज भी थी और उसकी कोरोनरी स्टेंटिंग भी हो चुकी थी।

यह मामला इलाज के लिहाज़ से एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उनके बाएं वेंट्रिकुलर इंजेक्शन फ्रैक्शन का स्तर केवल 18 प्रतिशत था। इससे स्टैंडर्ड एंटी- ॥श्वञ्च2 टारगेटेड थेरेपी से जुड़े जोखिम काफी बढ़ गए थे, क्योंकि ये थेरेपी दिल की कार्यक्षमता को और खराब कर सकती हैं। ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इमेजिंग स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल केयर टीम ने मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट डॉ अमृतजोत सिंह रंधावा की देखरेख में एक खास तौर पर तैयार की गई इलाज की रणनीति बनाई। डॉ रंधावा ने कहा कि मरीज़ की दिल की कमज़ोर हालत को देखते हुए, हमने नैनोपार्टिकल पैक्लिटैक्सेल कीमोथेरेपी के साथ-साथ गहन कार्डियक मॉनिटरिंग और बेहतर सपोर्टिव केयर का विकल्प चुना। मरीज़ ने कीमोथेरेपी के चार चक्र सफलतापूर्वक पूरे किए और इलाज का बहुत अच्छा असर दिखा। बाद में की गई पीईटी-सीटी जांच से पता चला कि मेटाबोलिक रूप से बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है और बीमारी का कोई सक्रिय लक्षण नहीं बचा था। खास बात यह है कि दिल की गंभीर बीमारी के बावजूद, महिला ने बिना किसी बड़ी जटिलता के इलाज को बहुत अच्छी तरह से सहन किया।

हमने बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित किया और मजबूत बाजार हिस्सेदारी वृद्धि के साथ दोहरे अंकों वाली, वॉल्यूम-आधारित वृद्धि हासिल की-तिवारी

मोगा 12 जून (मधु राजपूत)। नेस्ले इंडिया के श्री मनीष तिवारी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपने शुरुआती कुछ तिमाहियों के कार्यकाल पर नज़र डालते हुए, मुझे उस प्रगति और गति को लेकर गहरी जिम्मेदारी और विश्वास का अनुभव होता है, जिसे हम मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। इस भूमिका में आपको अपना पहला वार्षिक पत्र साझा करते हुए मुझे सम्मान का अनुभव हो रहा है। मैं अब तक की हमारी उपलब्धियों और उन प्राथमिकताओं के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमें उपभोक्ताओं की बेहतर सेवा करने, ग्राहकों के साथ अपनी साझेदारियों को और मजबूत बनाने, जिन समुदायों तक हमारी पहुंच है वहां साझा मूल्य सृजित करने तथा अपने शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी।मैं नेस्ले के उत्पादों के साथ बड़ा हुआ हूँ, इसलिए इस भूमिका में आना मेरे लिए एक बेहद व्यक्तिगत अनुभव जैसा है। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ मुझे हमारे मोहल्ले के किराना दुकानदार राजू की दुकान से मेरी पसंदीदा मिल्कमेड0कंडेंस्ड मिल्क का एक टिन लाने के लिए भेजती थीं।

रोजमर्रा के वे सरल पल आज भी मेरी यादों में बसे हुए हैं। अपने प्रतिष्ठित सफेद टिन से लेकर आधुनिक री-सीलेबल पाउच तक, मिल्कमेड0 समय के साथ विकसित हुआ है, लेकिन पीढ़ियों से भारतीय घरों का एक भरोसेमंद हिस्सा बना हुआ है। उत्पाद का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन भरोसा समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरता है। लगातार अच्छा प्रदर्शन शायद ही कभी एक साथ बहुत सारे काम करने से हासिल होता है।

यह कुछ सही निर्णयों, अनुशासित क्रियान्वयन और निरंतर सुधार की संस्कृति से प्राप्त होता है। उपभोक्ता कारोबार में, किसी भी तिमाही के दौरान ये काम करने के सामान्य तरीके प्रतीत हो सकते हैं। लेकिन समय के साथ ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहते। इनका प्रभाव लगातार बढ़ता जाता है।

संस्कृति और सनातन परंपराओं को मजबूत करती है निशान यात्रा : भगवानदास कबीरपंथी

भव्य निशान यात्रा के साथ गूंजा शहर, विधायक, चेयरमैन समेत गणमान्य लोगों ने लिया हिस्सा, बाबा श्याम के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल

तरावड़ी, 12 जून (छाया शर्मा) : एकादशी पर्व के पावन अवसर पर श्री श्याम सेवादार मंडल तरावड़ी द्वारा भव्य निशान यात्रा एवं बाबा श्याम के विशाल संकीर्तन का आयोजन श्रद्धा के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त किया।

श्री श्याम सेवादार मंडल के नेतृत्व में नगर खेड़ा तरावड़ी से श्री खाटू श्याम मंदिर तक भव्य निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े।

पूरे मार्ग पर भक्तिमय वातावरण बना रहा तथा श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। इसके उपरांत श्री खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम का भव्य संकीर्तन आयोजित किया गया, जिसमें भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया।

श्रद्धालु देर रात तक बाबा श्याम के भजनों पर झूमते रहे। कार्यक्रम में हल्के के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, पंजाबी सभा तरावड़ी के प्रधान राजीव नारंग, उद्योगपति अनिल नारंग, नगरपालिका तरावड़ी के चेयरमैन वीरेंद्र बंसल, जी.वी. राइस यूनिट के सीएमडी विनीत बंसल, समाजसेवी नरेश अरोड़ा, पार्षद नरेश गाबा, युवा समाजसेवी यश सलूजा, खाटू श्याम मंदिर से अशोक बंसल, अंकुर गर्ग सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर विधायक भगवानदास कबीरपंथी

ने कहा कि निशान यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि समाज को एकता, भाईचारे और सेवा भाव का संदेश देने का माध्यम भी है। ऐसे धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति और सनातन परंपराओं को मजबूत करने का कार्य करते हैं।

बड़ी संख्या में युवाओं एवं श्रद्धालुओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि समाज अपनी धार्मिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। श्री श्याम सेवादार मंडल के पदाधिकारियों ने सभी श्रद्धालुओं, सामाजिक संस्थाओं एवं नगरवासियों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य जारी रहेगा।

इस दौरान निशान यात्रा में आए हुए गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया।

पुलिस विभाग आम नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन की शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबंध है : चन्द्रमोहन

थाना बाबैन पहुंचे पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने नशा तस्करी के खिलाफ आमजन से मांगा सहयोग

बाबैन, 12 जून (राजेश कुमार) : कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने गुरुवार को थाना बाबैन का दौरा कर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनीं तथा पुलिस अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। थाना बाबैन पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन का लाडवा के डीएसपी निर्मल सिंह, थाना प्रभारी राजीव कुमार, मार्केट कमेटी बाबैन के चेयरमैन जसविंदर सिंह जस्सी, बाबैन के सरपंच संजीव सिंगला उर्फ गोल्डी, रामसरन माजरा के सरपंच प्रतिनिधि ओमप्रकाश, बाबैन के पूर्व सरपंच

विश्वजीत सिंह बिंदल, जितेंद्र गर्ग (गुग्गी) सहित बाबैन क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा फूल-मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन ने बाबैन थाना परिसर में पौधारोपण किया और लोगों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधे न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का आधार भी बनता है।

पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने थाना परिसर में जन सुनवाई के दौरान बाबैन क्षेत्र के विभिन्न गांवों एवं कस्बों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जिससे शिकायतकर्ताओं ने संतोष व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने कहा कि पुलिस विभाग आम नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा उनकी शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास एवं सहयोग का मजबूत रिश्ता अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमजन को बिना किसी भय के अपनी समस्याएं पुलिस के समक्ष रखनी चाहिए, ताकि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा समाज के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। नशे की लत युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रही है और परिवारों को भी प्रभावित कर रही है। इस समस्या से निपटने के लिए केवल पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति नशा तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने तथा उन्हें खेल, शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण में परिवार, शिक्षण संस्थान, सामाजिक संगठन और पुलिस प्रशासन सभी की समान भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बाबैन थाने का भी निरीक्षण किया और पुलिस रिकॉर्ड का अवलोकन भी किया।

पार्किंग के लिए आर्थिक सेवा की राशि से गुरुद्वारा साहिब के लिए खरीदी करीब 5 कनाल भूमि

कार्यकारिणी समिति मेंबर पलविंदर सिंह दरड और संत महापुरुष बाबा जोगा सिंह जी ने संगत का जताया आभार

तरावड़ी, 12 जून (छाया शर्मा) : हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अधीन ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाही नौवीं तरावड़ी के नाम करीब 5 कनाल भूमि की रजिस्ट्री करवाई गई। यह सारी कार्रवाई हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की कार्यकारिणी समिति मेंबर पलविंदर सिंह दरड और संत महापुरुष बाबा जोगा सिंह तरावड़ी की अगुवाई में हुई। इस भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए संत महापुरुष बाबा जोगा सिंह कार सेवा वाले की अपील पर इलाके की संगत ने आर्थिक रूप से सेवा करते हुए करीब 1 करोड़ 80 लाख रूपए की राशि एकत्रित की गई, जिसे भूमि की खरीद में प्रयोग किया गया। नीलोखेड़ी तहसील में भूमि रजिस्ट्री की सारी कार्रवाई की गई। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब में इस भूमि खरीद में सेसहयोग देने वाली संगत को गुरु घर की बक्शीश सिरोपा भेंट कर उनका सम्मान किया गया। संगत ने गुरुद्वारा साहिब में शीश नवाया और गुरु चरणों में अरदास की गई।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की कार्यकारिणी समिति मेंबर पलविंदर सिंह दरड ने बताया कि संत महापुरुष बाबा जोगा सिंह जी कार सेवा वाले के सहयोग से संगत से उगराही कर लगभग एक करोड़ 80 लाख रूपए एकत्रित किए गए थे। इलाके के अलग-अलग गांव की संगत में यह आर्थिक सेवा गुरु घर के लिए जमीन खरीदने के लिए की है।

इस भूमि पर गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग बनाई जाएगी। इस पार्किंग की वजह से गुरु घर में आने वाली संगत को वाहन खड़े करने की सुविधा मुहैया हो सकेगी। उन्होंने गुरु घर के लिए सेवा के रूप में आर्थिक सहयोग करने वाली संगत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। संत महापुरुष बाबा जोगा सिंह जी कार सेवा वालों ने भी संगत का आभार जताते हुए उनकी सुख समृद्धि के लिए गुरु चरणों में अरदास की। इस दौरान गुरुद्वारा मैनेजमेंट के मैनेजर नवजोत सिंह चीमा और बाबा गुरप्रीत सिंह ने भी संगत का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बाबा जसविंदर सिंह जी, सरपंच अमरजीत सिंह, अमरीक सिंह दरड, गुरनाम सिंह, जुझार सिंह, प्रगट किए कथावाचक, गुरप्रीत सिंह, गुरदीप सिंह रंभा, प्रताप सिंह ललयानी, गुरजीत सिंह, सरपंच रवि पखाना, गुरबाज सिंह, मनजीत सिंह, दिलबाग सिंह, हरजीत सिंह, नाजर सिंह, परविंदर सिंह समेत संगत मौजूद रही।

गांव दिल्लोवाली में आयोजित हुआ रात्रि प्रवास कार्यक्रम

गांव दिल्लोंवाली सहित आस-पास के दस गांवों में नहरी पानी परियोजना जल्द होगी पूरी, डीसी ने जारी किए निर्देश

कैथल, 12 जून (प्रवेश बहादुर) : वीरवार को गांव दिल्लोवाली में रात्रि प्रवास कार्यक्रम में डीसी अपराजिता ने लोगों की शिकायतें सुनीं और मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश दिए। गांव की सरपंच सोनिया देवी, वीरभान, सतपाल, ज्ञान चंद व राजपाल आदि ग्रामीणों ने फूल मालाओं व पुष्पगुच्छ के माध्यम से गांव में पहुंचने पर डीसी अपराजिता व अन्य अधिकारीगण का स्वागत किया। डीसी ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ-साथ गांव दिल्लोंवाली सहित आस-पास के दस गांवों के लिए नहरी पानी परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। डीसी अपराजिता ने सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद डीसी ने ग्रामीणों की गंभीरता से समस्याएं सुनी। गांव की सरपंच सोनिया देवी ने गांव की समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा। सरपंच ने कहा कि गांवों में बहुत से विकास कार्य हुए हैं, जिसमें गांव की सड़कें, गलियां, सोलर लाइट, सीसीटीवी कैमरे व अन्य विकास कार्य किए गए हैं। गांव के तालाब में से पानी की निकासी की समस्या का समाधान करवाया जाए। साथ ही तालाब का सौंदर्यीकरण भी करवाया जाए। गांव के स्कूल से लेकर जनरल चौपाल तक तारों को बदला जाए। गांव में आरओ प्लांट लगवाया जाए। सूखा व गीला कचरा के लिए वाहन उपलब्ध करवाया जाए। इन सभी समस्याओं के निपटान के लिए डीसी अपराजिता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। ग्रामीण सतपाल सहित अन्य ने गांव में नील गाय यानि रोज की संख्या ज्यादा होने व इससे फसलों में काफी नुकसान होने की शिकायत रखी। जिसके लिए डीसी ने जिला वन अधिकारी कार्यालय को समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने गांव में ही पेंशन दिलवाए जाने की सुविधा की मांग की। जिस पर डीसी ने समाज कल्याण अधिकारी को इस समस्या के समाधान के निर्देश दिए। लोगों ने गांव में आवारा कुतों की संख्या बढ़ने बारे शिकायत रखी। जिसके समाधान के लिए डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। गांव वासियों ने 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों की भी प्राइवेट बस में पूरी टिकट लिए जाने की शिकायत की। जिसके सममाधान के लिए डीसी ने आरटीए को निर्देश जारी किए। गांव वासियों ने पेयजल की पाइप लाइन बिछाने की मांग की। जिस पर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गांव दिल्लोंवाली सहित आस-पास के दस गांवों के लिए नहरी पानी परियोजना पूरी की जा रही है। डीसी ने इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। गांव वासियों ने सरकारी स्कूलों में चौकीदार की व्यवस्था, सिलेंडर की उपलब्धता गांव में 45 दिन की बजाए शहरों की तर्ज पर 25 दिन में दिए जाने की मांग की। डीसी ने जिला शिक्षा अधिकारी को चौकीदार के लिए विभाग मुख्यालय में लिखे जाने व डीएफएससी को जल्द सिलेंडर दिए जाने के लिए विभाग मुख्यालय लिखे जाने के निर्देश जारी किए। डीसी अपराजिता ने मौके पर सभी शिकायतों के संदर्भ में संबंधित विभागों के अधिकारियों से जानकारी हासिल की और कहा कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करवाएं। इसमें कोई भी लापरवाही न बरतें। इनके अलावा अन्य ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, विवाह शगुन योजना आदि समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। जिस पर डीसी अपराजिता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करें और इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव के नए आयाम स्थापित किए : पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार

सोनीपत, 12 जून (ब्यूरो) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकारी नीतियों व जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब उन्होंने देशवासियों से आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करने का संकल्प लिया था। पिछले 12 वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिनका परिणाम आज पूरे देश के सामने है। उन्होने कहा कि वर्ष 2014 में भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत आर्थिक नीतियों और देशवासियों के सहयोग का परिणाम है।

500 वर्षों का सपना हुआ साकार

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण भारत की सांस्कृतिक चेतना और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सदियों से करोड़ों लोगों की यह भावना थी कि भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक सपना साकार हुआ। आज अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुकी है।

धारा 370 हटाकर मजबूत किया राष्ट्रीय एकीकरण

विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय था। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि इस प्रावधान को हटाना संभव नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इसे सफलतापूर्वक हटाकर देश में एक संविधान, एक निशान और एक विधान की भावना को मजबूत किया गया।

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई गति :-पंवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पहले देश अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर विदेशों पर निर्भर था, लेकिन आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत रक्षा उपकरणों और सैन्य तकनीक के निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में निर्मित रक्षा उपकरणों का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है।

जनकल्याणकारी योजनाओं से बदली करोड़ों लोगों की जिंदगी

पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं तथा आने वाले वर्षों में भारत विश्व के अग्रणी देशों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा। इस मौके पर खरखौदा से विधायक पवन खरखौदा, भाजपा वरिष्ठ नेता प्रदीप सांगवान, भाजपा जिलाध्यक्ष गोहाना बिजेन्द्र मलिक, भाजपा जिलाध्यक्ष सोनीपत अशोक भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित

हिसार, 12 जून (ब्यूरो) : लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा रही सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा को लेकर उपायुक्त महेंद्र पाल ने शुक्रवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि वे आमजन की शिकायतों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। नागरिकों को एक ही समस्या के लिए बार-बार शिकायत दर्ज करवाने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही प्रशासनिक कार्यों की वास्तविक सफलता का पैमाना है। इससे पूर्व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, आईएएस द्वारा सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत उपायुक्त महेंद्र पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के समाधान के बाद पोर्टल पर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायत से संबंधित सभी तथ्य, जांच रिपोर्ट एवं समाधान की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनी रहे। उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं भी समय-समय पर जनता से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सिंह, अतिरिक्त निगमायुक्त प्रदीप हुड्डा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बंद नाले पर चला निगम का हथौड़ा, कमिश्नर ने खुद खड़े होकर हटवाए अवैध कब्जे

जगाधरी बस स्टैंड के बाद नगर निगम ने देवी भवन बाजार में बंद नाले को खुलवाकर की जल निकासी

यमुनानगर, 12 जून (दिनेश कुमार) : मानसून के दौरान शहर को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम पूरी तैयारियां कर रहा है। ट्विनसिटी (यमुनानगर-जगाधरी) के नालों की सफाई का काम इन दिनों युद्धस्तर पर जारी है। जल निकासी के रास्ते में आने वाले अवैध कब्जों, अतिक्रमण और अवरोधकों को पूरी सख्ती के साथ ढहाया जा रहा है। जगाधरी बस स्टैंड के पास पांच साल से बंद पड़े नाले को खोलने के बाद जगाधरी के देवी भवन बाजार में दुकानदारों द्वारा बंद किए गए नाले को खुलवाया। यहां दुकानदारों द्वारा बंद किए गए एक बड़े नाले को कर्मचारियों ने हथोड़ों से भारी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। खास बात यह रही कि नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद और अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार ने खुद मौके पर डटकर पूरी कार्रवाई की निगरानी की। निगम कर्मियों ने हथौड़ों की मदद से नालों पर पक्के तौर पर बनाई गई अवैध स्लैब और अन्य अवरोधकों को तोड़कर बंद पड़े नाले को पूरी तरह चालू किया। इसके बाद नाले से भारी मात्रा में सिल्ट और कचरा निकालकर पानी की निकासी को सुचारू किया गया। मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह के नेतृत्व में बनी टीम ने नालों की सफाई कराकर जल निकासी कराई। इस नाले के खुलने से अब देवी भवन बाजार समेत आस-पास के कई बड़े इलाकों को इस मानसून में जलभराव की गंभीर समस्या से मुक्ति मिलेगी।

एजेंसी व अधिकारियों को सख्त हिदायत

देवी भवन बाजार के अलावा निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने सिविल लाइन रोड, राजेश कॉलोनी सहित शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। राजेश कॉलोनी में पुलिया के पास जाल में फंसे कचरे को साफ कराया गया। उन्होंने मौके पर मौजूद निगम अधिकारियों

और सफाई एजेंसी को निर्देश दिए कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में जहां कहीं भी नालों पर अवैध कब्जे, स्लैब या किसी भी प्रकार का अवरोध है, उसे बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। काम में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जहां भी नालों में कचरा है, उसे तुरंत साफ कराए। बारिश से पहले सभी नालों की गहराई तक सफाई करना सुनिश्चित करें।

नालों को डस्टबिन न बनाएं जनता, निगम के वाहनों में डालें कचरा : आयुक्त

निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने शहरवासियों और दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि नालों को साफ रखना सिर्फ निगम की नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लोग नालों के ऊपर या अंदर ठोस कचरा, पॉलीथिन, कपड़े और प्लास्टिक बैग न फेंकें। इससे न केवल नाले जाम होते हैं, बल्कि नाला ब्लॉक होने से गंदा पानी सड़कों पर आने से महामारी फैलने का खतरा भी बना रहता है। आमजन से अपील है कि व नालों को डस्टबिन न बनाए। घर व दुकान से निकलने वाले कचरे को अलग अलग एकत्रित करके निगम के वाहनों में डाले।

भारतीय सेना भर्ती रैली एवं आउटरीच कार्यक्रमों को लेकर बैठक आयोजित

हिसार, 12 जून (ब्यूरो) : भारतीय सेना भर्ती रैली की व्यवस्थाओं, आउटरीच कार्यक्रमों तथा व्यापक जन-जागरूकता अभियान के संबंध में उपायुक्त महेंद्र पाल तथा सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल दीपक चौहान ने एक बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक में एसीयूटी विवेक यादव भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान भर्ती रैली से संबंधित प्रशासनिक सहयोग, जन-जागरूकता गतिविधियों तथा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं तक सेना भर्ती संबंधी जानकारी पहुंचाने तथा पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया एवं उपलब्ध अवसरों के प्रति जागरूक करने पर बल दिया गया। उपायुक्त महेंद्र पाल ने प्रस्तावित गतिविधियों के सफल आयोजन हेतु जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में बताया गया कि सेना एवं नागरिक प्रशासन के बीच निरंतर समन्वय के माध्यम से युवाओं तक भर्ती संबंधी जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकेगी।

हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने सतीश गुप्ता, व्यापारियों में खुशी का माहौल

- सतीश गुप्ता ने नायब और मनोहर सहित भाजपा शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार, बोले : व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करना रहेगी प्राथमिकता

करनाल, 12 जून (रविन्द्र मलिक) : हरियाणा सरकार द्वारा सतीश गुप्ता को हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का वाइस चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर व्यापारी वर्ग और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। गुरुवार को करनाल स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। विभिन्न व्यापारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने उन्हें बुके देकर तथा मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। नव-नियुक्त वाइस चेयरमैन सतीश

गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि सरकार ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है। जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उसका निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है और उनकी समस्याओं के समाधान तथा हितों की रक्षा के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। सतीश गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारियों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल तथा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और व्यापारियों के हितों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सतीश गुप्ता ने कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से उठाया जाएगा। बाजारों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ व्यापारियों तक पहुंचाने तथा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के सुझावों और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

वहीं सतीश गुप्ता की नियुक्ति पर कई व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। शुभचिंतकों ने कहा कि सतीश गुप्ता लंबे समय से सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं तथा उन्हें विभिन्न वर्गों की समस्याओं का अच्छा अनुभव है। ऐसे में उनकी नियुक्ति से व्यापारी वर्ग की आवाज को और मजबूती मिलेगी।

शरीरदान कर मानवता की मिसाल बने महेंद्र इन्सां, परिवार को किया गया सम्मानित

रतिया, 12 जून (अमन सेठी) : रतनगढ़ ब्लॉक के गांव महमदकी निवासी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी शरीरदानी महेंद्र इन्सां के नमित नामचर्चा का आयोजन किया गया। नामचर्चा के दौरान जहां शरीरदानी महेंद्र इन्सां को साध-संगत ने श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं उनके परिवार को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नामचर्चा की शुरुआत प्रेमी सेवक जगजीवन ने की हरियाणा स्टेट के सच्चे नम्र सेवादार हरदीप इन्सां ने बताया कि 4 अप्रैल को महेंद्र इन्सां शरीर छोड़ चले गए थे। देहरादून मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए महेंद्र इन्सां के शरीर को दान किया गया था। आज नाम चर्चा कर श्रद्धांजलि दी गई। यह उनके परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानी की है। साध-संगत को इस तरह के कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर बघेल, प्रीत, बलवंत, रवि, राजेंद्र सरपंच, पवन, जसबीर, अंग्रेज, केवल, बिल्लू, कृष्ण, दर्शन, तरसेम, गुरमीत, जगपाल व रिश्तेदार व ब्लाक रतनगढ़ की साध संगत उपस्थित थी।

12 साल- विश्वास, विकास और जन कल्याण के

जिला के 2 लाख 91 हजार से अधिक लोगों को मिल रहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ

प्रो-एक्टिव व्यवस्था लागू, 45 हजार 381 लाभार्थियों की पेंशन बिना दफ्तर के चक्कर काटे स्वत: हुई शुरू

करनाल, 12 जून (मीनाक्षी देवी) : केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आमजन के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। जिनका सीधा लाभ जिले के पात्र लोगों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा भी आमजन के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रो-एक्टिव व्यवस्था लागू की गई है जिससे पात्र नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इस प्रणाली के तहत स्वत: सत्यापन के बाद पेंशन घर बैठे ही शुरू कर दी जाती है। वर्ष 2022 से अब तक 45 हजार 381 लोगों की घर बैठे ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनी है। उन्हें न तो योजना के लिए आवेदन करना पड़ा और न ही कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े। वहीं सरकार ने पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में कई बार पेंशन की राशि को बढ़ाया है। सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी दिशा में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रो-एक्टिव मोड में लागू किया गया है, जिससे पात्र व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। पीपीपी में दर्ज आंकड़ों के आधार पर पात्रता पूरी होने पर विभाग स्वयं कार्रवाई कर लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ता है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा को 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही दिव्यांगता की श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगजन योजनाओं का लाभ उठा सकें। जिला समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिले में 2 लाख 90 हजार से अधिक लाभार्थी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जिले में 1 लाख 34 हजार 84 वृद्धजन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत प्रतिमाह 3,200 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 61 हजार 857 विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को भी प्रतिमाह 3,200 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार 53 हजार 464 महिलाओं को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2,100 रुपये का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार 15 हजार 189 निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, 9 हजार 930 दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन, 5 हजार 307 विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता तथा 2 हजार 51 महिलाओं को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा 673 मंदबुद्धि बच्चों, 461 कैंसर रोगियों तथा 8 बौना एवं 1 किन्नर लाभार्थी को भी सरकार द्वारा नियमित आर्थिक सहायता दी जा रही है। एसिड अटैक पीड़ितों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार 8 हजार रुपये से 14 हजार 400 रुपये तक मासिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। सरकार द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले उन परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल किया गया है जिनके बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं, जिन्होंने सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करते हुए 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं या निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित ग्रेड हासिल किए हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा 17,491 निराश्रित बच्चों को प्रतिमाह 4,600 रुपये तक (2,300 रुपये प्रति बच्चा) की आर्थिक सहायता सरल पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है। इसी प्रकार विदुर एवं अविवाहित वित्तीय सहायता सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई श्रेणी में जिले के 4,097 विदुर व अविवाहित व्यक्तियों को 3,200 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता के तहत 3,469 लाभार्थी, कैंसर पीड़ितों के लिए 360 लाभार्थी, तथा स्कूल न जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों के लिए 892 लाभार्थियों को मासिक पेंशन दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग का मुख्य लक्ष्य मुख्यमंत्री के अंत्योदय विजन को धरातल पर उतारना है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बिना किसी बिचौलिए या परेशानी के उसका हक सीधे उसके बैंक खाते में मिल सके।

बलदेव ग्रोहा के चेयरमैन बनने पर पूर्व विधायक, नपा चेयरमैन, सरपंचों व गणमान्य लोगों ने दी बधाई

रतिया, 12 जून (अमन सेठी) : भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा को चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। उनकी नियुक्ति के बाद उनके निवास पर पूर्व विधायक लक्ष्मण अप्पा, नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि महेश खत्रा, अग्रवाल सभा प्रधान प्रमोद बंसल, मनोनीत पार्षद सुखविंदर गोयल, समाजसेवी सोनू ग्रोवर, सरपंच दिनेश भारती, संदीप सोहल, जॉर्जदीप सिंह, हरमेश शर्मा व अन्य गणमान्य लोगों के साथ बलदेव ग्रोहा के निवास पर पहुंचे। सभी ने फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें चेयरमैन बनने की बधाई दी। गणमान्य लोगों ने कहा कि बलदेव ग्रोहा का चेयरमैन बनना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। वे लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और आम जनता की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र का विकास नई ऊंचाइयों को छुएगा।

इस मौके पर बलदेव ग्रोहा ने सभी का आभार जताया और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उसे वे पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाएंगे। क्षेत्र की जनता की सेवा ही उनकी प्राथमिकता रहेगी।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता

करनाल, 12 जून (प्रवीन) : उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को 71 हजार रुपये की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। वहीं विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है। यदि नवविवाहित दंपती दिव्यांग हैं तो उन्हें भी 51 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की शादी के लिए और ऐसे दिव्यांग जोड़ों को जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो, उसे भी अब 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराना जरूरी है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुगम बनाया गया है ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वैदिक युग में शिक्षा के सही उद्देश्य क्या थे

आज की शिक्षा और पहले की शिक्षा में बहुत अंतर थी आज मोबाइल और कोचिंग के अलावा बच्चे प्रैक्टिस पर जोड़ नहीं देते ना ही बड़ो का बात मानते हैं, पहले पेपर लिक भी नहीं होता संस्कार था अब सब ख़त्म हो रहा है वैदिक काल (लगभग 1700-900 ई.पू.।) से भारत में शिक्षा की शुरुआत मान सकते हैं। 'वैदिक शिक्षा' शब्द का प्रयोग इस अवधि में प्रयुक्त शिक्षण पद्धति के अर्थ में किया जाता है। एक व्यापक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग उस शिक्षा पद्धति के लिए किया जाता है जो पूर्व वैदिक काल में प्रारंभ हुई और लगभग 550 ई। (गुप्त साम्राज्य के पतन तक) विकसित होती रही। इसे 'ब्राह्मण शिक्षा-पद्धति', 'शिक्षा की हिंदू प्रणाली' और शिक्षा की 'गुरुकुल प्रणाली' भी कहा जाता है। भारतवर्ष मैं रहने वाली सर्वप्रथम जाति आर्य थी और वैदिक संस्कृति आर्यों की अपनी संस्कृति थी 7 वैदिक-संस्कृति सत्य, सनातन है और वेद को अनादि अथवा ईश्वरीय माना गया है , क्योंकि मनुष्य और उसकी सभ्यता के बारे में सबसे प्राचीन इतिहास भी इसी संस्कृति की देन है 7 जिसमें ऋषियों द्धारा मानव समाज को ब्यवस्थित तरीके से चलाने के लिये मर्यादित आचरण की ब्यवस्था दी गयी 7वैदिक शिक्षा-प्रणाली की ख़ास विशेषता थी की पूर्व वैदिक युग में शिक्षा के गुरुकुल [शाब्दिक अर्थ शिक्षक का घर '] की प्रणाली। छात्रों को शिक्षा के पूरे काल के लिए शिक्षक और उनके परिवार के साथ रहना आवश्यक था। कुछ गुरुकुल एकांत वन-क्षेत्रों में होते थे, लेकिन सिद्धांत एक ही था विद्यार्थियों को गुरु (शिक्षक) / गुरु और उनके परिवार के साथ रहना होता था। यह प्रणाली लगभग 2500 वर्षों तक यथावत चलती रही। पाठशालाओं तथा शिक्षण संस्थाओं का विकास बहुत बाद में हुआ शिक्षा के उद्देश्य का पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10 वें मंडल में पाया जाता है। इस मंडल के एक सूक्त में कहा गया है कि विद्या का उद्देश्य वेदों तथा कर्मकांड के ज्ञान के अतिरिक्त समाज में सम्मान प्राप्त करना, सभा-समिति में बोलने में सक्षम होना, उचित-अनुचित का बोध आदि है। इससे प्रतीत होता है की पूर्व वैदिक युग में शिक्षा के उद्देश्य व्यावहारिक थे। बाद में, उपनिषद काल में, ज्ञान का उद्देश्य अधिक सूक्ष्म हो गया। विद्या को दो भागों में बांटा गया - परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या में प्राय: समस्त पुस्तकीय तथा व्यावहारिक ज्ञान आ गया। केवल ब्रह्म विद्या को परा विद्या माना गया। परा विद्या श्रेष्ठ मानी गई क्योंकि उससे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष शिक्षा का अंतिम उद्देश्य हो गया। लेकिन यह लक्ष्य आदर्श ही रहा होगा, न की व्यावहारिक, क्योंकि मोक्ष सभी के लिए साध्य नहीं हो सकता। इतिहासकार ए.एस.अल्तेकर ने वैदिक शिक्षा के व्यावहारिक उद्देश्य बताये हैं जो निम्नलिखित हैं। 1) चरित्र निर्माण- सत्यवादिता , संयम , व्यक्तिगत शील , सफाई , शांत स्वभाव और उदारता आदि अच्छे चरित्र के गुण किसी भी पेशे - पुरोहित , शिक्षक , चिकित्सक , राजसेवक, व्यापारी या सैनिक - के लिए बुनियादी आवश्यकता के रूप में प्राचीन ग्रंथों में निर्धारित किये गए हैं। शिक्षा का उद्देश्य इन गुणों का विकास करना था। मनुस्मृति में कहा गया है कि निर्मल चरित्र का ब्राह्मण सभी वेदों का ज्ञान रखने वाले दुश्चरित्र ब्राह्मण से अच्छा होता है। शिक्षा आरम्भ करने के पूर्व उपनयन संस्कार होता था जिसमें भावी विद्यार्थी को नैतिक आचरण के नियमों का पालन करने का उपदेश दिया जाता था। इसी तरह शिक्षा के समापन पर भी गुरु उपदेश देता था। उदाहरण के लिए तैत्तिरीय उपनिषद से दीक्षांत भाषण एक अंश उद्धृत है -सच बोलो, धर्म का आचरण करो, वेदों का प्रतिदिन अभ्यास करो, माता पिता को देवतुल्य समझो, गुरु को देवतुल्य समझो। अतिथि को देवतुल्य समझो। 2) व्यक्तित्व का विकास- प्रत्येक शिक्षार्थी को आत्मनिर्भरता , आत्म - संयम और जीवन में वर्ण और आश्रम के अनुरूप आचरण करने का कौशल सिखाया जाता था। विद्यार्थी भिक्षा मांगकर और शारीरिक श्रम करके अपना और गुरु के परिवार का भरण-पोषण करते थे। इससे आत्म-निर्भरता उत्पन्न होती थी। संयम विद्यार्थी-जीवन ही नहीं समस्त जीवन का अनिवार्य अंग था और शिक्षा जीवन में इस पर बहुत बल दिया जाता था। अपने वर्ण से सम्बंधित कार्य कुशल ढंग से कर पाने की सामर्थ्य शिक्षा द्वारा दी जाती थी। साथ ही यह भी सिखाया जाता था कि विभिन्न आश्रमों [गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास] में किस तरह आचरण करना होगा। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा गया है की गुरु, शिक्षार्थी को दुबारा जन्म देता है, अर्थात उसका मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक कायाकल्प कर देता है। 3) कार्य-क्षमता और नागरिक जिम्मेदारी का विकास- शिक्षा को गृहस्थ जीवन की भूमिका माना जाता था। गृहस्थ के अतिरिक्त सभी अन्य आश्रमों वाले व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए गृहस्थ पर निर्भर होते थे। इस तरह गृहस्थ न केवल अपने परिवार बल्कि अन्य वर्णों का भी पालन करता था। गुरु शिक्षार्थी को समाज में अपनी यह भूमिका निभाने में सक्षम बनाता था। इसके अतिरिक्त समाज को चलाने के लिए आवश्यक राजसेवक, न्यायाधीश, व्यापारी, पुरोहित तथा अन्य कुशल व्यक्ति गुरुकुलों द्वारा ही तैयार किये जाते थे।

बीई एवं बीटेक के मध्य अंतर समझकर ही दाखिला लें

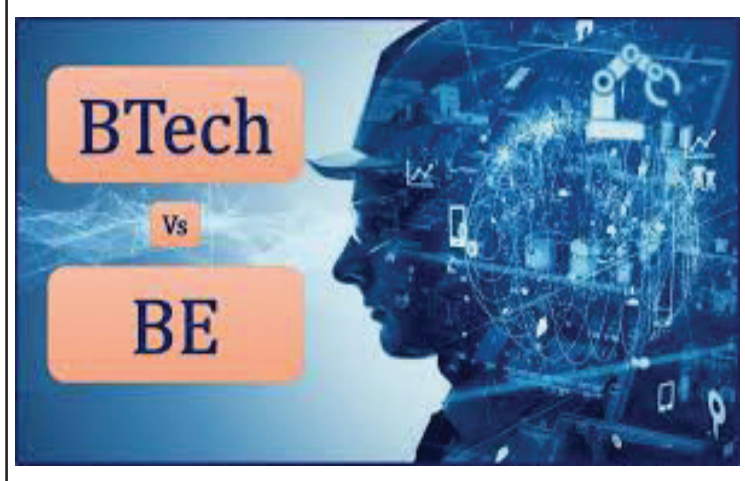

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाले युवाओं के लिए बीई और बीटेक का अंतर जानना जरुरी है। तभी वे अंदाजा लगा सकेंगे कि कौन सा कोर्स उनके कॅरियर के लिए अच्छा रहेगा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई एक पारंपरिक डिग्री कोर्स है, जोकि इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल और बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को थ्योरी बेस्ड नॉलेज अधिक दी जाती है। जिससे कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ सकें। वहीं इस कोर्स में प्रैक्टिकल और लैब वर्क भी होते हैं। लेकिन इस कोर्स की थ्योरी की गहराई अपेक्षाकृत अधिक होती है। बीई और बीटेक दोनों ही डिग्रियां इंजीनियरिंग की फील्ड में समान मान्यता प्राप्त है। इन दोनों कोर्स में फर्क सिर्फ कॅरियर गोल्स और पढ़ाई के तरीके में होता है। ऐसे में सही कोर्स का चुनाव करके आपके लक्ष्य, रुचि और पढ़ाई के प्रति रुख पर निर्भर करता है।

बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी

यह कोर्स प्रैक्टिकल और एप्लिकेशन-ओरिएंटेड डिग्री है। इसमें तकनीकी पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस कोर्स में इंडस्ट्री में चलने वाले ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजी और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आदि पर फोकस किया जाता है। इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार बीटेक कोर्स डिजाइन किया जाता है। जिससे कि स्टूडेंट्स सीधे तौर पर जॉब के लिए तैयार हो सकें।

बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स थ्योरी और फंडामेंटल्स पर अधिक केंद्रित होता है। वहीं बीटेक में इंडस्ट्री स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है। बीई कोर्स में एकेडमिक और रिसर्च बेस्ड स्टडी अधिक की जाती है जबकि बीटेक में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क पर अधिक फोकस होता है।

बीई का सिलेबस थोड़ा ट्रेडिशनल होता है और बीटेक का सिलेबस इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से बार-बार अपडेट होता रहता है।

कैसे चयन करें

अगर आपका रुझान इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को गहराई से समझने में और फ्यूचर में रिसर्च या फिर हायर एजुकेशन किए जाने में हैं, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। वहीं अगर आप पढ़ाई के फौरन बाद किसी टेक्निकल जॉब में जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं, तो फिर बीटेक कोर्स आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा।

ऑनलाइन एआई कोर्स का युवाओं को मिल रहा लाभ

आजकल आर्टिफीशियल इंटेलीजैंस (एआई)की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप भी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार के कोर्स कर आगे बढ़ सकते है । कई कंपनियां कुछ कम अवधि के ए आई के शार्ट टर्म एआई कोर्स आयोजित करती हैं जिन्हें पूरा कर आप भी इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। इन कोर्स की फीस 500 रुपए से लेकर 15 हजार रुपए तक हो सकती है। इनमें से कुछ कोर्स फ्री होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए कंपनियां फीस लेती हैं। गूगल समेत कई कंपनियों की तरफ से कई तरह के एआई कोर्स जारी किए गए हैं। यह कोर्स ऑनलाइन और पूरी तरह फ्री हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए यह कोर्स आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि यह कोर्स अंग्रेजी में होते हैं और आपको थोड़ी-बहुत कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। बाकि इन कोर्स को करने के लिए किसी खास तरह की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आप यह कोर्स को अपनी रेज्यूमे में जोड़कर अच्छी नौकरी की तलाश पूरी कर सकते हैं। लार्ज लैग्वेज मॉडल्स - इस कोर्स को करने के बाद आप भी चैट जपीटी जैसा प्लैटफॉर्म बना सकते है। इस कोर्स में आपको यह सिखाया जाता है कि किस तरह से चैट जपीटी जैसे प्लेटफॉर्म पर इमेज और कंटेंट क्रिएट किये जाते हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल बना सकते हैं। यह किसी भी कंटेंट को दूसरी भाषा में ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनटों में लंबे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। लार्ज लैग्वेज मॉडल्स कोर्स में यह भी बताया व सिखाया जाता है कि आप किस तरह प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग की सहायता से आउटपुट पर नियंत्र पा सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 8 घंटे की है। इमेज जनरेटर - इमेज जनरेटर का कोर्स कर आप आई की सहायता से कैसा भी कोई भी फोटो बना सकते हैं। इस कोर्स में आप यह भी सीख सकते हैं कि कम रिजॉल्यूशन वाली फोटो को हाई रिजॉल्यूशन में कैसे बदलें। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी का चेहरा भी डिजाइन कर सकते हैं और लैंडस्केप इमेज भी तैयार कर सकती हैं। इस कोर्स में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर इमेज, स्केच और कार्टून आदि बनाने की ट्रेनिंग दी भी जाती है। इस कोर्स की अवधि 8 घंटे की है।

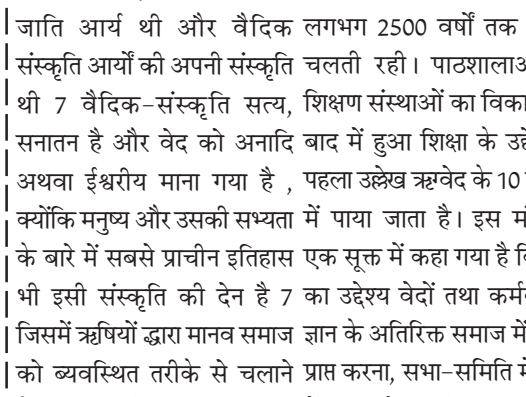

विश्व की सबसे कठिन परीक्षा में शामिल है यूपीएससी, जेईई

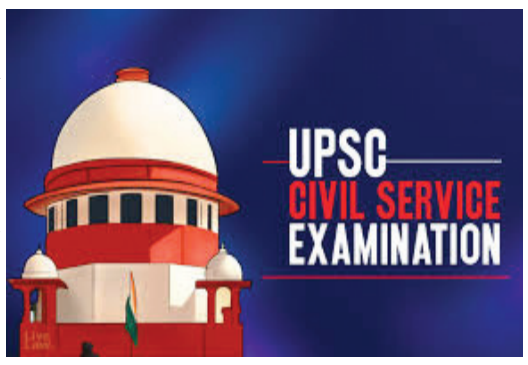

मौजूदा दौर में शिक्षा और करियर, दोनों ही प्रतियोगिता पर आधारित हैं। लाखों स्टूडेंट्स हर साल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इनमें से कुछ परीक्षाओं में सफल हो पाना बहुत मुश्किल है। इनका पास प्रतिशत इतना कम होता है कि कई बार सालों की मेहनत के बाद भी लोग इनमें सफल नहीं हो पाते। चाहे वह भारत की यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा हो या चीन की गोवाकाओ परीक्षा युवा सफलता की गारंटी के बिना अपनी जिंदगी के कई साल इनकी तैयारी में झोंक देते हैं।

दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट, मेंटल प्रेशर से निपटना और लगातार आत्मविश्वास बनाए रखना भी सफल होने के लिए बहुत जरूरी होता है। यही कारण है कि इन्हें क्रैक करने वाले लोग न सिर्फ बुद्धिमान माने जाते हैं, बल्कि उनका धैर्य और जज्बा भी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। विश्व की सबसे कठिन परीक्षाएं

1. गाओकाओ परीक्षा (चीन)

कठिनाई रैंक- 1

चीन की राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा। 2025 में लगभग 1 करोड़ 33 लाख 50 हजार स्टूडेंट्स ने यह परीक्षा दी। चीन के कॉलेज/यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का दर लगभग 85 फीसदी है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेजों में दाखिला मिलता है।

2 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (भारत)

कठिनाई रैंक- 2

डिटेल-यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है। हर साल लगभग 1.3 मिलियन (13 लाख) उम्मीदवार यूपीएससी सीएसई के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन का दर करीब 0.1 फीसदी है। लाखों अभ्यर्थी 1000 के करीब पदों के लिए यह परीक्षा देते हैं।

3 जेईई एडवांस्ड (भारत)

कठिनाई रैंक- 3

डिटेल-जेईई मेंस में टॉप 2.5 लाख रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी जेईई एडवांस्ड के पात्र माने जाते हैं। आईआईटी और अन्य टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए इसे पास करना जरूरी है। 2025 में 1,87,223 आवेदन, 1,80,422 उपस्थित, 54,378 क्वॉलिफाई- लगभग 30.1 फीसदी सफल.

4 चार्टर्ड अकाउंटेंसी (भारत)

कठिनाई रैंक- 4

डिटेल-सीए परीक्षा 3 चरणों में होती है- सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल. हर साल लाखों उम्मीदवारों में से गिनती के उम्मीदवार ही इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। आम तौर पर सीए परीक्षा का पास प्रतिशत बहुत कम रहता है. कई युवा सालों तक इसकी तैयारी करते हैं।

5 सीएफए (अमेरिकी संस्थान द्वारा आयोजित)

कठिनाई रैंक- 5

डिटेल- सीएफए यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्त परीक्षा है। इसका आयोजन अमेरिकी संस्था करती है। सीएफए परीक्षा केंद्र दुनियाभर में बनाए जाते हैं। लेवल 1 में इसकी सफलता दर 45 प्रतिशत तक है। सेकंड और थर्ड लेवल तक यह दर कम होती जाती है।

इबर अपराध बढ़ने से एथिकल हैकर की मांग बढ़ी

आजकल जिस प्रकार से साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए एथिकल हैकर की मांग तेजी से बढ़ रही है। एथिकल हैकर का काम अपने कौशल का इस्तेमाल कर कंपनियों और लोगों को साइबर हमले से बचाना हैं। एथिकल हैकर कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाकर साइबर हमले रोकते हैं। आजकल जिस प्रकार से साइबर अपराध बढ़ रहा है, उससे एथिकल हैकर्स की भी मांग भी तेजी से बढ़ी है। सरकारी क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र सभी में इनके लिए अवसर काफी ज्यादा है। हालात ये है कि जरुरत जितनी है उससे इसके पेशेवरों की तादाद काफी कम है। ऐसे में यह एक फायदेमंद, रोमांचक और महत्वपूर्ण कॅरियर बन गया है। ऐसे में अगर आप भी कंप्यूटर और हैकिंग में रुचि रखते हैं, तो आप एथिकल हैकिंग की बारीकियां सीखकर इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। एथिकल हैकर बनने के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी सभी अहम जानकारियां होनी चाहिए। इसमें स्क्रिप्टिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग का अच्छा ज्ञान, प्रोग्रामिंग पर अच्छी पकड़, सर्वर और सर्च इंजन, डाटाबेस की अच्छी समझ, नई तकनीकों से उसे लगातर अपडेट रहना होगा।

जब परीक्षा व्यवस्था स्वयं परीक्षा में असफल होने लगे

- डॉ नीलम महेंद्र

रात के दो बजे हैं। देश के किसी छोटे शहर में एक विद्यार्थी अभी भी जाग रहा है। मेज पर खुली हुई पुस्तकें हैं, दीवार पर समय-सारिणी चिपकी है और मोबाइल फोन महीनों से लगभग निष्क्रिय पड़ा है। घर के बाकी सदस्य सो चुके हैं, पर उसकी आँखों में नींद नहीं, भविष्य है।

वह अकेला नहीं है।-भारत में हर वर्ष लगभग चार करोड़ विद्यार्थी विभिन्न बोर्ड, प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। केवल सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में 40 लाख से अधिक और नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में 20 लाख से अधिक विद्यार्थी भाग लेते हैं। इन संख्याओं के पीछे केवल आँकड़े नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आकांक्षाएँ, त्याग और संघर्ष छिपे हुए हैं। इसीलिए भारत में परीक्षा कभी केवल परीक्षा नहीं रही। यह योग्यता और अवसर के बीच का सबसे महत्वपूर्ण पुल रही है।

लेकिन आज यही पुल दरकता हुआ दिखाई दे रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं का रद्द होना, तकनीकी विफलताएँ, मूल्यांकन संबंधी विवाद और परीक्षा प्रबंधन पर उठते प्रश्न यह संकेत दे रहे हैं कि समस्या किसी एक संस्था या एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। हम एक गहरे संस्थागत संकट के सामने खड़े हैं,विश्वास के संकट के सामने।

स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह रही कि उसने शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता का रास्ता बनाया।

किसी गाँव का साधारण छात्र डॉक्टर बन सकता है।

किसी किसान की बेटी प्रशासनिक अधिकारी बन सकती है।

किसी मजदूर का बेटा राष्ट्रीय संस्थानों तक पहुँच सकता है।

इस व्यवस्था की सफलता का आधार केवल पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि विश्वास है। यदि किसी परीक्षा में बैठा विद्यार्थी यह मानता है कि उसकी मेहनत ही सफलता का निर्धारण करेगी, तब वह वर्षों तक संघर्ष करता है। लेकिन यदि उसे यह लगने लगे कि परिणाम योग्यता से अधिक व्यवस्था की कमजोरियों पर निर्भर हैं, तो पूरी प्रणाली का नैतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि परीक्षा प्रणाली पर संकट केवल शिक्षा का संकट नहीं होता; वह सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अवसर का संकट भी बन जाता है। पिछले दशक में सरकारों ने डिजिटल तकनीक को पारदर्शिता का पर्याय मान लिया है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण को आधुनिकता की पहचान माना गया।

लेकिन एक मूल प्रश्न अक्सर अनुत्तरित रह जाता है,क्या तकनीक स्वयं भरोसा पैदा करती है? नहीं! तकनीक केवल एक उपकरण है। उसका चरित्र उस व्यवस्था से तय होता है जो उसे संचालित करती है।

यदि टेंडर प्रक्रिया अपारदर्शी हो, यदि साइबर सुरक्षा की स्वतंत्र जाँच न हो, यदि शिकायतों को गंभीरता से न लिया जाए और यदि तकनीकी परियोजनाओं की निगरानी केवल कागजों पर हो, तो अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर भी अविश्वास पैदा कर सकता है।

सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उत्पन्न विवाद इसी व्यापक समस्या की ओर संकेत करता है। प्रश्न केवल तकनीकी नहीं हैं। प्रश्न यह हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लागू होने वाली प्रणाली के लिए निगरानी तंत्र कितना सक्षम था, जोखिम मूल्यांकन कितना गहन था और जवाबदेही कितनी स्पष्ट थी।

जब एक छात्र व्यवस्था से बड़ा दिखाई देने लगे तो क्या ही खा जाए!

हाल के घटनाक्रम का सबसे असाधारण पक्ष यह नहीं कि विवाद हुआ। असाधारण पक्ष यह है कि अनेक प्रश्न एक छात्र द्वारा सार्वजनिक रूप से उठाए गए। यह घटना प्रतीकात्मक है। यह बताती है कि सूचना के इस युग में नागरिक अधिक जागरूक हो रहा है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि संस्थागत सतर्कता कहीं न कहीं कमजोर पड़ी है।

सवाल यह नहीं कि किसी छात्र ने प्रश्न क्यों उठाया।

सवाल यह है कि वे प्रश्न पहले किसी निगरानी समिति, किसी तकनीकी ऑडिट या किसी प्रशासनिक समीक्षा में क्यों नहीं उठे?

जब व्यवस्था के बाहर खड़ा व्यक्ति व्यवस्था के भीतर बैठे लोगों से अधिक सजग दिखाई देने लगे, तब समस्या व्यक्ति की नहीं, प्रणाली की होती है। भारत में चिकित्सा शिक्षा केवल एक पेशा नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा का माध्यम भी मानी जाती है। यही कारण है कि लाखों विद्यार्थी वर्षों तक नीट की तैयारी करते हैं।

कोचिंग उद्योग का आकार अब हजारों करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। अनेक परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की तैयारी पर खर्च करते हैं। कुछ विद्यार्थी घर छोड़कर कोटा, दिल्ली, पटना, प्रयागराज और हैदराबाद जैसे शिक्षा केंद्रों में वर्षों तक रहते हैं। ऐसे में यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, तो उसका प्रभाव केवल परिणामों पर नहीं पड़ता। **उसका प्रभाव मनोविज्ञान पर पड़ता है।**

एक छात्र अपनी मेहनत पर संदेह नहीं करता, लेकिन वह व्यवस्था पर संदेह करना शुरू कर देता है।

और किसी भी राष्ट्र के लिए इससे अधिक खतरनाक स्थिति नहीं हो सकती। प्रशासनिक विफलता की चार परतें

इन घटनाओं को केवल तकनीकी त्रुटि मान लेना वास्तविक समस्या से आँखें मूँद लेना होगा। पहली समस्या है,जमीनी वास्तविकता से दूरी। निर्णय अक्सर उन कमरों में लिए जाते हैं जहाँ आँकड़े पहुँचते हैं, अनुभव नहीं। दूसरी समस्या है,अनुपालन संस्कृति।

हमारे यहाँ यह देखने की प्रवृत्ति अधिक है कि नियमों का पालन हुआ या नहीं; यह देखने की प्रवृत्ति कम है कि परिणाम सही निकला या नहीं। तीसरी समस्या है,तकनीकी निर्भरता। अनेक प्रशासनिक अधिकारी उत्कृष्ट नीति-निर्माता होते हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा, डिजिटल संरचना और डेटा गवर्नेंस की जटिलताओं को समझने के लिए उन्हें विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथी और सबसे गंभीर समस्या है,जवाबदेही का अभाव। जब सफलता का श्रेय संस्थाएँ लेती हैं, तो विफलता की जिम्मेदारी भी संस्थाओं को ही लेनी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ अक्सर इसका उल्टा होता है। परीक्षा उद्योग का बढ़ता आकार और घटता विश्वास

भारत का परीक्षा तंत्र अब एक विशाल आर्थिक संरचना भी बन चुका है।

डीसी और एसएसपी से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल, तरसेम भट्ठल मामले में कार्रवाई की मांग

बरनाला, 12 जून (बघेल सिंह धालीवाल) मुलाजिम डिफेंस कमेटी बरनाला के आह्वान पर आज जिले की सभी कर्मचारी, पेंशनर, किसान, मजदूर तथा जनवादी संगठनों की एक बैठक स्थानीय डीसी कॉम्प्लेक्स के पार्क में आयोजित की गई।बैठक को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं करमजीत बिहला, राजीव कुमार, रविंदर शर्मा, निर्मलजीत सिंह, सेवानिवृत्त नेता कौर सिंह, हाकम सिंह नूर तथा मोहन सिंह छन्ना ने कहा कि 9 जून 2026 को पुलिस प्रशासन द्वारा सेवा केंद्र बरनाला के कर्मचारियों को धरने से उठाने के दौरान पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन के प्रदेश महासचिव तरसेम भट्ठल के साथ एसएचओ बरनाला लखविंदर सिंह ने दुर्व्यवहार किया तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इससे एक कर्मचारी संगठन के नेता की गरिमा को ठेस पहुंची है।बैठक में मुलाजिम डिफेंस कमेटी के प्रमुख नेताओं दर्शन चीमा, हरिंदर मलियां, अनिल कुमार, तजिंदर तेजी, सुखजीत सिंह, बीकेयू उगराहां के चमकौर सिंह नैणेवाल, कमलजीत कौर, बीकेयू डकौंदा के बाबू सिंह खुड्डीकलां, क्रांतिकारी किसान यूनियन के मनजीत राज, महिमा सिंह धनौला, मोहन सिंह रूड़ेके, बीकेयू लखोवाल के कैप्टन हरदीप सिंह, मजदूर मुक्ति मोर्चा के गुरप्रीत रूड़ेके, जम्हूरी अधिकार सभा के डॉ. सोहन सिंह माझी, इंकलाबी केंद्र के सुखविंदर ठीकरीवाला, तीर्थ दास, मोहन सिंह, अमरजीत सिंह तथा बलवंत सिंह ने कहा कि एसएचओ लखविंदर सिंह ने साथी तरसेम भट्ठल के साथ दुर्व्यवहार किया, धक्कामुक्की की, अपशब्द कहे और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया।उन्होंने कहा कि यह धरना सेवा केंद्र कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में लगाया गया था और तरसेम भट्ठल केवल संगठनात्मक स्तर पर कर्मचारियों के साथ हो रहे कथित अन्याय का विरोध करने के लिए वहां पहुंचे थे।बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि जल्द ही मुलाजिम डिफेंस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त (डीसी) बरनाला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बरनाला से मुलाकात करेगा तथा संबंधित पुलिस अधिकारी को अपनी गलती का अहसास करवाने की मांग करेगा।नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन द्वारा तरसेम भट्ठल के सम्मान की बहाली के लिए उचित कदम नहीं उठाया गया, तो संगठन की ओर से कड़ा संघर्ष और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जगत गुरु नानक देव ओपन यूनिः पटियाला का क्षेत्रीय केन्द्र संघेड़ा कालेज में शिक्षा प्रदान कर रहा

बरनाला, 12 जून (बघेल सिंह धालीवाल) गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, संघेड़ा में संचालित जगत गुरु नानक देव ओपन यूनिवर्सिटी, पटियाला के मालवा क्षेत्रीय केंद्र द्वारा नौकरीपेशा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधाएं अत्यंत सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत विद्यार्थियों को केवल परीक्षा देने के लिए कॉलेज आना होता है, जबकि पूरी पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जाती है।सत्र 2026-27 को ध्यान में रखते हुए संस्था के प्रधान भोला सिंह विरक के मार्गदर्शन में जगत गुरु नानक देव ओपन यूनिवर्सिटी संबंधी एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के वर्तमान शिक्षा प्रणाली में महत्व तथा विद्यार्थियों द्वारा घर बैठे और नौकरी करते हुए इसका लाभ उठाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।बैठक के दौरान इस बात पर भी विचार किया गया कि वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर संस्था के प्रधान भोला सिंह विरक ने कहा कि समय के साथ शिक्षा के तरीकों में बड़े बदलाव आए हैं और ऑनलाइन शिक्षा ने विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।इसके बाद संस्था के प्रिंसिपल डॉ. सरबजीत सिंह कुलार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के कौशल और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है।इस चर्चा में संस्था के प्रधान भोला सिंह विरक, संस्था के उपप्रधान भोला सिंह गिल, प्रिंसिपल डॉ. सरबजीत सिंह कुलार, वाइस प्रिंसिपल मैडम मनदीप कौर, स्कूल प्रिंसिपल मैडम रविंदर कौर जौंधा, प्रो. मित्तू पाठक आदि मौजूद रहे।

कालका में आज आयोजित होगी भव्य कव्वाली नाइट, श्रद्धालुओं में उत्साह

कालका, 12 जून (अख्तर फ़ारूक़ी/अजीत सिंह) : कालका रेलवे रोड स्थित रविदास मंदिर में आज 13 जून 2026, शनिवार को मीरा बाबा की याद में भव्य कव्वाली नाइट का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। आयोजकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज दोपहर 12 बजे भंडारे का आयोजन होगा, शाम 4 बजे मेहंदी रस्म आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रसिद्ध कव्वालों द्वारा सूफियाना कव्वालियों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने की अपील की है। इस आयोजन में सहारनपुर से आने वाले कव्वाल अपनी प्रस्तुति देंगे। यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश देगा।

शराब ठेके के सेल्समैन पर हमला करके चोटें मारने के मामले में दो आरोपी काबू

कैथल/राजौंद, 12 जून (प्रवेश बहादुर/नरेश कुमार) : नंदकरण माजरा स्थित शराब ठेके के सेल्समैन पर हमला करके चोटे मारने के मामले में एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के आदेशानुसार एसएचओ राजौंद इंस्पेक्टर रामनिवास व सीआईऐ कलायत इंचार्ज एएसआई मनीष कुमार की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को काबू कर लिया गया। काबू किए गए आरोपियों में सोंगल निवासी कमल तथा बालू निवासी राममेहर शामिल है।

एसएचओ राजौंद इंस्पेक्टर राम निवास ने बताया की गांव सौंगल निवासी राजेश कुमार की शिकायत अनुसार वह नंदकरण माजरा स्थित शराब ठेके पर सेल्समैन के रूप में कार्यरत है। शिकायतकर्ता के अनुसार 7 जून की रात करीब 10 बजे उसे राममेहर उर्फ बालू निवासी गांव बालू का फोन आया, जिसने उसे तैयार रहने की बात कही। कुछ देर बाद गांव सौंगल निवासी कमल, नसीब तथा राममेहर निवासी बालू शराब ठेके पर पहुंचे। आरोप है कि तीनों ने आते ही उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी तथा उसे दुकान से बाहर निकलने के लिए कहा। शिकायतकर्ता के अनुसार राममेहर ने उसका गला पकड़ लिया, जबकि कमल ने अपने हाथ में लिए डंडे से उसकी बाईं बाजू पर वार किया। इसके बाद आरोपी उसे दुकान के अंदर ले गए और डंडों तथा चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान आरोपी लगातार मारपीट करते रहे, जिससे उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उसने शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी उसे पुलिस कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। जिस बारे थाना राजौंद में मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को निशानदेही के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया। नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसएचओ ने कहा की कानून व्यवस्था भंग करने वाले एवं हिंसक घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आठवीं कक्षा के इतिहास पाठ्यक्रम में जोड़कर सिख गुरुओं का किया सम्मान

मूनक, 12 जून (जय भगवान) : गुलाब सिंह गांव मूनक ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया कि उन्होंने सिख समाज से किया गया वादा पूरा करते हुए कक्षा 8वीं के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरु साहिबानों तथा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के इतिहास को शामिल किया है। सिख गुरुओं की शिक्षाएं मानवता, समानता, सेवा, त्याग, भाईचारे और न्याय का संदेश देती हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद साहब जी तक सभी गुरु साहिबानों ने मानवीय मूल्यों को ऊंचा उठाने और समाज को नई दिशा देने में अतुलनीय योगदान दिया है। उनकी कुर्बानियां और उपदेश केवल सिख समाज के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

इसी प्रकार बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। उनका जीवन संघर्ष, वीरता, देशभक्ति और जनकल्याण की भावना का प्रतीक है। स्कूली पाठ्यक्रम में इस इतिहास को शामिल करने से बच्चों को अपनी महान विरासत, इतिहास और संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा। नई पीढ़ी गुरु साहिबानों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझेगी और अच्छे नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सिख समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए इस महत्वपूर्ण निर्णय को अमली रूप दिया। यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और हमारी साझा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को और अधिक सशक्त बनाए। वाहेगुरु जी से प्रार्थना है कि वे हरियाणा को निरंतर प्रगति और समृद्धि प्रदान करें तथा समाज के कल्याण के लिए ऐसे जनहितैषी निर्णय निरंतर लिए जाते रहें।

देर रात आई तेज आंधी से टूटा बिजली का पोल, वार्ड 8 और 9 में छाया अंधेरा

राजौंद, 12 जून (नरेश कुमार) : राजौंद में देर रात आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वार्ड नंबर 8 और 9 को जोड़ने वाली मुख्य लाइन का एक भारी-भरकम बिजली का खंभा बीच से टूटकर धराशायी हो गया। खंभा टूटने और तारें टूटने के कारण पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे दोनों वार्डों में पूरी रात अंधेरा पसरा रहा। इस अचानक आए संकट से वार्ड नंबर 8 और 9 के सैकड़ों परिवार बेहद परेशान हैं। रात भर लोग उमस और भीषण गर्मी के कारण सो नहीं सके। सुबह होते ही संकट और गहरा गया क्योंकि बिजली न होने की वजह से घरों में पानी की सप्लाई भी पूरी तरह ठप हो गई। रात 8 बजे से अगले दिन 4 बजे तक भी बिजली आपूर्ति बाधित रही।जिससे दोपहर के समय बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का गर्मी के मारे बुरा हाल रहा। वार्ड की महिला रजनी, किताबो ने बताया कि बिजली न होने से इन्वर्टर भी डाउन हो चुके हैं। फ्रिज में रखा सामान खराब हो रहा है। हम बिजली विभाग के अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे स्थिति की गंभीरता को समझें। परेशान वार्डवासियों ने बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों से पुरजोर अपील की है कि युद्धस्तर पर काम चलाकर जल्द से जल्द नया पोल खड़ा किया जाए और टूटी हुई तारों को ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल की जाए।

बलदेव ग्रोहा बने हरियाणा सरकार में चेयरमैन

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की कमान संभालेंगे

रतिया, 12 जून (अमन सेठी) : फतेहाबाद जिले के रतिया निवासी बलदेव सिंह ग्रोहा को हरियाणा सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उन्हें हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बलदेव ग्रोहा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इससे पहले वह बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। संगठन में उनकी सक्रियता और जमीनी पकड़ को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें यह दायित्व सौंपा है। नियुक्ति के बाद बलदेव ग्रोहा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के विश्वास पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। निगम की योजनाओं को धरातल पर उतारकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उनकी इस नियुक्ति पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। रतिया ब्लॉक समिति चेयरमैन विकास भानीखेडा व राधा कृष्ण मंदिर कमेटी प्रधान राजेश सेतिया ने नवनियुक्त चेयरमैन बलदेव ग्रोहा को गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। सभी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में निगम सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा।

शहर को साफ-सुन्दर बनाने में करें शहरवासी करें नगरपालिका का सहयोग : सनमीत कौर आहूजा

नीलोखेड़ी, 12 जून (सुरेश कुमार मिड्ढा) : शहर को साफ सुन्दर बनाने में नगरपालिका के साथ-साथ शहरवासियों को सहयोग होना बेहद जरूरी है ताकि शहर को ओर अधिक स्वच्छ बनाया जा सके। इसी कड़ी में वार्ड नं. 9 और 10 में नगरपालिका अध्यक्ष सनमीत कौर आहूजा और नगरपालिका सचिव डा. राहुल सैनी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में नगरपालिका अध्यक्ष व दोनों वार्ड के पार्षद नीता देवी और अमित कुमार शैली ने घर-घर जाकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर हमें अपने नीलोखेड़ी शहर को स्वच्छ बनाना है तो सबसे पहले घर से निकलने वाले सुखे और गीले कचरे को अलग-अलग करना होगा। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष सनमीत कौर आहूजा ने चार प्रकार के डस्टबीन हरे, नीले, लाल और काले रंग के डस्टबीन की पहचान करवाई साथ ही नीलोखेड़ी शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और सुन्दर बनाने में और आस-पास सफाई व्यवस्था बनाए रखने में नगरपालिका का सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर नगरपालिका से सफाई इंचार्ज राजबीर, प्रेरक नरेश कुमार, संगीता रानी, सफाई दरोगा सुनील कुमार, विनोद कुमार, तथा सुगम स्वच्छता से रवि कुमार उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता

करनाल, 12 जून (प्रवीन) : उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है।

उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को 71 हजार रुपये की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

वहीं विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है। यदि नवविवाहित दंपती दिव्यांग हैं तो उन्हें भी 51 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की शादी के लिए और ऐसे दिव्यांग जोड़ों को जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो, उसे भी अब 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराना जरूरी है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुगम बनाया गया है ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक http://shadi.edisha.gov.in/ पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भाजपा की नीतियों और नेतृत्व के प्रति बढ़ रहा जनता का विश्वास : रेणु बाला गुप्ता

तरुण चुघ और डॉ. सतीश पूनिया के निर्विरोध निर्वाचन पर जताया हर्ष

करनाल, 12 जून (संदीप रोहिला) : भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ के मध्य प्रदेश तथा हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया के राजस्थान से राज्यसभा सदस्य के निर्वाचित होने पर पार्टी संगठन में हर्ष का माहौल है। महापौर रेणु बाला गुप्ता और भाजपा के पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष बृज गुप्ता ने दोनों नेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह निर्विरोध निर्वाचन भाजपा की मजबूत सांगठनिक संरचना, पारदर्शी कार्यशैली और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।

महापौर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में पार्टी निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है। अनुभवी नेताओं का राज्यसभा में पहुंचना संगठन की नीति और दृष्टि को और मजबूती प्रदान करेगा। भाजपा के पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष बृज गुप्ता ने कहा कि दोनों नेताओं का निर्विरोध निर्वाचन दर्शाता है कि भाजपा आज देश की सबसे विश्वसनीय और व्यापक जनाधार वाली राजनीतिक शक्ति बन चुकी है, जहां कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक एकजुटता का मजबूत संदेश जाता है। दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि राज्यसभा में इन वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति राष्ट्रहित, विकास और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी तथा संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

धान की सीधी बिजाई करने पर 4500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि : डॉ. वजीर सिंह

करनाल, 12 जून (संदीप रोहिला) : कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा लगातार गिरते भूजल स्तर को बचाने और किसानों की लागत कम करने के लिए 'धान की सीधी बिजाई' (डीएसआर) योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत जल संरक्षण और कृषि लागत को कम करने के उद्देश्य से जो किसान पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई के बजाय सीधी बिजाई करते है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा 4500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि धान की सीधी बिजाई से धान की खेती करने पर पारंपरिक रोपाई की तुलना में लगभग 25 से 35 प्रतिशत तक कम पानी लगता है। नर्सरी तैयार करने, पौधों को उखाड़ने और रोपाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें मजदूरों और समय दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि खेतों में पानी भरकर न रखने (पडलिंग न करने) से मीथेन गैस का उत्सर्जन घटता है और भूमि की पानी ग्रहण करने की क्षमता बढती है। पौधों को उखाडकर दोबारा लगाने पर जो झटका या तनाव लगता है, सीधी बिजाई में ऐसी कोई समस्या नही होती, जिससे फसल का विकास अच्छा होता है। उन्होंने बताया कि सीधी बिजाई के दौरान किसानों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिएं। उन्होंने बताया कि बुवाई से पहले खेत को लेजर लैंड लेवलर से समतल अवश्य करें। सीधी बिजाई में खरपतवार की समस्या अधिक होती है इसके लिए बुवाई के तुरंत बाद या अगले 24 से 48 घंटो के भीतर (खेत मे पर्याप्त नमी होने पर) दवा का छिडक़ाव करें।

धान की सीधी बिजाई की सफलता की कहानी किसानों की जुबानी : उपनिदेशक ने बताया कि किसान राजीव कुमार आस-पास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। वह धान की सीधी बिजाई करने के लिए किसानों का उत्साहवर्धन करने के साथ उनके साथ अपना अनुभव व ज्ञान भी साझा करते हुए उनका मार्गदर्शन करते है। इन्ही की तरह किसान राजेश कुमार गांव सरवन माजरा खण्ड इन्द्री ने भी कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन से 2.5 एकड़ से धान की सीधी बिजाई की शुरुआत की थी जोकि अब 20 एकड़ तक पहुंच चुकी है। इनके अनुभव अनुसार भी धान की सीधी बिजाई करने पर उपरोक्त सभी लाभ किसान को प्राप्त होते है। उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने जिला के सभी किसानों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक धान की सीधी बिजाई करके जल संरक्षण की मुहिम में साथ दें, अपनी लागत कम करें एवं समय बचायें तथा विभाग द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भी लाभ उठायें।

बीएलए-2 प्रशिक्षण शिविर का 13 जून को असंध में होगा आयोजन : गोगी

असंध, 12 जून (दलसिह मान) : एसआईआर अभियान को लेकर सालवन रोड स्थित श्री सनातन धर्मशाला में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक का आयोजन 13 जून को किया जाएगा। जिसमें एसआईआर के अंतर्गत असंध हल्के के सभी बीएलए-2 का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष करनाल राजेश वैद्य करेगें। बैठक में शहरी जिलाध्यक्ष पराग गाबा व जिला उपाध्यक्ष मित्रपाल शर्मा विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत करेगें। उपरोक्त जानकारी नगर की नई अनाज मंडी में पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। गोगी ने सभी से बैठक में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन सुरजीत राणा, पूर्व सिटी प्रधान जितेन्द्र चोपड़ा, युवा अध्यक्ष असंध जतिन बिंदल, सुदामा चोचड़ा, अनिल फफड़ना, सुल्तान जबाला सहित अन्य मौजूद रहे।

जनसुनवाई में महापौर ने दिखाई सक्रियता, मौके पर किया समस्याओं का निपटारा

करनाल, 12 जून (संदीप रोहिला) : नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान महापौर रेणु बाला गुप्ता ने एक बार फिर आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने आम जन की समस्याएं पूरी एकाग्रता और विस्तार से सुनीं। इस दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान करते हुए नागरिकों को राहत प्रदान की गई। जनसुनवाई के दौरान माहौल पूरी तरह जनकेंद्रित और परस्पर संवादात्मक रहा। महापौर रेणु बाला गुप्ता ने प्रत्येक नागरिक की बात को गंभीरता से सुना। इसी आधार पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। महापौर ने कहा कि नगर निगम की कार्यशैली का केंद्र बिंदु नागरिक सुविधा और समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए। विशेष रूप से शहर की स्वच्छता, जल निकासी, सड़क व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था जैसी मूलभूत सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर निगरानी और सुधार कार्य जारी हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि शहर के विकास में जनता की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो नागरिक सीधे प्रशासन के सामने अपनी बात रखें, ताकि समाधान की दिशा में और अधिक तेजी से आगे बढ़ा जा सके। महापौर ने दोहराया कि समस्या नहीं, समाधान की नीति के साथ नगर निगम की टीम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी सकारात्मक सोच के साथ करनाल को स्वच्छ, आधुनिक एवं आदर्श शहर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

12 साल बाद बेगुनाह साबित कोर्ट ने पति को दोषमुक्त किया

नई दिल्ली 12 जून (निस) दिल्ली की एक अदालत ने करीब 12 साल पुराने मामले में आरोपी पति को बेगुनाह करार देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने माना कि उस पर लगे गंभीर आरोप मेडिकल साक्ष्यों की कसौटी पर टिक नहीं पाए। अदालत ने कहा कि एमएलसी रिपोर्ट दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने करीब 12 साल पुराने मामले में आरोपी पति को बेगुनाह बताया। अदालत ने गौरव आनंद को आपराधिक धमकी, मारपीट, दुष्कर्म के लिए उकसाने व अन्य गंभीर आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता महिला के गंभीर आरोप मेडिकल साक्ष्यों की कसौटी पर टिक नहीं पाए। अदालत ने कहा कि घटना के तुरंत बाद तैयार की गई मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट में न तो मारपीट के कोई निशान मिले और न ही महिला ने डॉक्टर को ऐसी किसी हिंसा की जानकारी दी, जबकि शिकायत में उसने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। इस बुनियादी विरोधाभास ने पूरे मामले को संदेहास्पद बना दिया और यही मेडिकल रिपोर्ट आरोपी की बेगुनाही का सबसे मजबूत आधार साबित हुई। मामला वर्ष 2014 का है। शिकायत के मुताबिक, एक महिला ने अपने पति गौरव आनंद और उसके साथियों सोनू बंगालन, तरुण सोनी और अफसाना खातून के खिलाफ शाहदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति उसे जबरन देह व्यापार में धकेल रहा था। विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी बेटी को छत से फेंकने की धमकी दी, उसे बंधक बनाया और चाकू की नोंक पर उसके साथ दुष्कर्म कर मारपीट की गई।

अविवाहित वयस्कों में सहमति से बने संबंध से साबित नहीं होता खराब चरित्र - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली 12 जून (संजय बंसल) सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंध को, उस संबंध में शामिल लोगों के चरित्र के बारे में प्रतिकूल धारणा बनाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड को एक ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश देते हुए की, जिसका पुलिस कांस्टेबल पद पर चयन एक असफल प्रेम संबंध से जुड़े आपराधिक मामले में संलिप्तता के कारण रद कर दिया गया था। पीठ ने कहा, 'दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंध उस संबंध में शामिल लोगों के चरित्र के बारे में प्रतिकूल धारणा बनाने का आधार नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो अविवाहित वयस्कों को सहमति से अपनी पसंद का संबंध रखने से रोकता हो। न्यायालय ने उम्मीदवार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल के पद पर उसकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने उनकी नियुक्ति इस आधार पर रद कर दी थी कि 2014 में उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का जो मामला दर्ज किया गया था, वह नैतिक पतन को दर्शाता है। यह मामला पड़ोसी के साथ संबंध से जुड़ा है और दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद 2015 में लोक अदालत में इसका निपटारा हो गया था। आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता और पीड़िता पड़ोसी थे और लगभग चार साल तक उनके बीच संबंध थे। पीठ ने कहा, 'हर रिश्ता शादी में तब्दील नहीं होता। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता शादी में तब्दील नहीं हुआ, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि एक पक्ष ने दूसरे को धोखा दिया है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ गांजा बरामद

नई दिल्ली 12 जून (निस) सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया, जिसके बैग से लगभग 2.43 करोड़ रुपये मूल्य का संदिग्ध गांजा बरामद किया गया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैंकॉक से आ रहे उस यात्री को बुधवार को एक्स-रे जांच और उसके सामान की विस्तृत तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान उसके बैग से हरे रंग के मादक पदार्थ से भरे आठ पॉलीथीन पाउच बरामद हुए। बयान में बताया गया कि बरामद किए गए पदार्थ का वजन 6,939.5 ग्राम था। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला कि यह पदार्थ प्रथम दृष्टया गांजा (मारिजुआना) है। बयान में कहा गया कि जब्त किए गए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 2.43 करोड़ रुपये है। यात्री को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और मादक पदार्थ के साथ उसकी पैकिंग सामग्री को आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया।

सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए मादक पदार्थों के स्रोत और इनके संभावित गंतव्य का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है और दोषियों का जल्द पता लगाया जाएगा।

दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम के बाहर कई राउंड फायरिंग लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी

नई दिल्ली 12 जून (निस) राजधानी के पश्चिम विहार इलाके में पंजाबी गायक गुरु रंधावा के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने जिम को निशाना बनाते हुए करीब सात राउंड गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने जिम के बाहर पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से जिम के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। वहीं एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस ऑडियो में खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाला अनिल पंडित नामक व्यक्ति कथित रूप से यह कहता सुनाई दे रहा है कि गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग इसलिए कराई गई क्योंकि उनकी अभिनेता सलमान खान से नजदीकियां बढ़ रही थीं और सलमान खान गैंग का दुश्मन है।

दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में होगी 41 किमी की वृद्धि

नई दिल्ली 12 जून (संजय बंसल) दिल्ली और एनसीआर के अन्य शहरों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए मेट्रो विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक मेट्रो के तीन और कॉरिडोर शुरू होने की उम्मीद है। इसमें मजेंटा लाइन का जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मार्ग विस्तार के दो हिस्से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक और मजलिस पार्क से आरके आश्रम मार्ग के साथ ही गोल्डन लाइन के एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर शामिल है। इनके शुरू होने से मेट्रो के नेटवर्क में लगभग 41 किमी की वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च, 2019 को मेट्रो के चौथे चरण अंतर्गत मजलिस पार्क-मौजपुर (पिंक लाइन), जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मार्ग (मजेंटा) और एरोसिटी-तुगलकाबाद (गोल्डन) लाइन को स्वीकृति दी थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मार्च, 2024 को इसी चरण के अंतर्ग चौथे चरण के अंतर्गत दो और नए कॉरिडोर लाजपत नगर-साकेत जी-ब्लाक इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ (पहले ग्रीन लाइन अब इसे मजेंटा लाइन में शामिल किया गया है) को स्वीकृति प्रदान की थी। पिछले वर्ष जनवरी में जनकपुरी पश्चिम-कृष्ण पार्क एक्सटेंशन पर परिचालन शुरू किया गया था। वहीं, इस वर्ष आठ मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिंक लाइन के मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर के साथ ही मजेंटा लाइन के दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक के हिस्से का उद्घाटन किया था। इससे पूर्वी और पश्चिम दिल्ली की अन्य हिस्सों से मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं, गोल्डन लाइन के एरोसिटी- तुगलकाबाद कारिडोर के भी इस वर्ष शुरू होने की बात कही जा रही है। इससे फरीदाबाद और दक्षिणी दिल्ली की तरफ से एयरपोर्ट आने-जाने वालों को सुविधा होगी।

दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को पल्सर सवारों ने दिखाया ठेंगा

नई दिल्ली 12 जून (संजय बंसल) दिल्ली में कल बदमाशों ने एक बार फिर दिनदहाड़े वारदात कर लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिया। दरअसल बदमाशों ने चांदनी चौक स्थित कूचा घासीराम में डेढ़ करोड़ रुपये देने जा रहे एक कंपनी के कर्मचारियों से लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपियों ने पिस्टल तान कर्मचारियों से कैश वाला बैग लूटा और मौके से फरार हो गए। घटना नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में हुई। पुलिस मामले में लूट का केस दर्ज छानबीन कर रही है। लोकल पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें भी मामले की जांच में जुटी हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है। कंपनी में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों तक की भूमिक की जांच की जा रही है। पूरी संभावना है कि वारदात में किसी जानकार का हो सकता है या फिर बदमाशों ने पूरी तरह रेकी कर इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया मामले पर चुप्पी साधे हुए थे।

सीएम सैनी का दावा..

पृष्ठ एक का शेष ..सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वन रैंक-वन पेंशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और सीएए जैसे अनेक युग-परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता, आदित्य-एल1 मिशन तथा गगनयान मिशन की तैयारियां भारत की वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी आत्मविश्वास का प्रमाण हैं। अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति और युवा सशक्तिकरण में ऐतिहासिक उपलब्धियां - मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2014 में भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था था, जबकि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वैश्विक महामारी, युद्ध, आर्थिक मंदी और आपूर्ति श्रृंखला संकट जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं को आर्थिक संबल मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में डिजिटल क्रांति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यूपीआई के माध्यम से भारत विश्व में डिजिटल भुगतान का नेतृत्व कर रहा है तथा विश्व के लगभग 56 प्रतिशत डिजिटल लेन-देन अकेले भारत में हो रहे हैं।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया गया है।

कांग्रेस का प्रदर्शन....जाँच का ही उल्लेख करना पड़ता है। उन्होंने देश के 80 साल के इतिहास में पहली बार एक गैर-संज्ञेय अपराध के नोटिस के आधार पर उम्मीदवारी खारिज किया जाना बताया।वहीं कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने दिन को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया।

उन्होंने कहा कि भाजपा जहाँ 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की बात करती है, वहीं वह अपनी तीन राज्यसभा सीटों पर एक भी महिला को मौका नहीं देती। और जब कांग्रेस मौका देती है, तब उस खत्म करने में पूरी ताकत लगा देती है। उन्होंने भाजपा पर विधायक खरीदकर वोटिंग से बचने का आरोप भी लगाया। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की बात अब स्पष्ट रूप से दिख रही है।

दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर यातायात पुलिस का बड़ा अभियान

नई दिल्ली 12 जून (निस) राजधानी की सड़कों को अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या से मुक्त कराने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और एमसीडी ने संयुक्त रूप से चार दिवसीय विशेष अभियान चलाया। 3 से 6 जून तक चले इस अभियान के दौरान दिल्ली के 144 संवेदनशील स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए गए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 55 हजार से अधिक चालान जारी किए गए। एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) विजयंता आर्य गोयल के मुताबिक, यह अभियान विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवीजन) के निर्देश पर संचालित किया गया। इसका उद्देश्य सड़कों की क्षमता बढ़ाना, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ट्रैफिक को सुचारु बनाना और निर्धारित पार्किंग स्थलों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना था।

डीयू के सत्यवती कॉलेज का छात्र निकला कॉलेजों में गांजा सप्लाई करने वाला

नई दिल्ली 12 जून (निस) दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेज समेत कई कालेजों में में नशीले पदार्थ की आपूर्ति करने वाले सत्यवती कालेज के एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने छात्र को 195 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा (आर्गेनिक गांजा) के साथ विजय नगर से पकड़ा है। आसानी से पैसा कमाने की चाहत में आरोपित डिलीवरी ब्वाय बनकर सत्यवती कालेज समेत कई कालेजों में नशीले पदार्थ की आपूर्ति करता था। आरोपित छात्र सत्यवती कालेज में सांध्य पाली में बीए (आठवें सेमेस्टर) का छात्र है।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली के मायापुरी में स्टील कटिंग फैक्ट्री में लगी आग

नई दिल्ली 12 जून (निस) मायापुरी में स्टील कटिंग एवं पैकिंग सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री में बृहस्पतिवार को भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग पहली और दूसरी मंजिल पर फैल गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, लगभग 500 वर्ग गज क्षेत्र में बनी यह इमारत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दो मंजिलों वाली है, जिसमें कुछ हिस्से अस्थायी तथा कुछ स्थायी निर्माण के हैं। आग की तीव्रता के कारण भवन का कुछ हिस्सा भी ढह गया। मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। साथ ही आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चल सका है।

आरोपी के नाबालिग होने पर उठे सवाल, जेजेबी में होगी निर्णायक सुनवाई

नई दिल्ली 12 जून (निस) द्वारका के उत्तम नगर, हस्तसाल में होली के दिन हुई चर्चित तरुण हत्याकांड में आरोपित के नाबालिग होने के दावे पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मामले में 11 जून को जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सुनवाई में आरोपित की वास्तविक उम्र को लेकर फैसला हो सकता है, जिससे पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। दरअसल, द्वारका कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) रजत गोयल की अदालत ने जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा 8 अप्रैल को पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें आरोपित को नाबालिग माना गया था। अदालत ने पाया कि आरोपित की उम्र से संबंधित दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां हैं और उपलब्ध रिकार्ड की पर्याप्त जांच किए बिना नाबालिग होने का निष्कर्ष निकाल लिया गया था। इसके बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई और आयु निर्धारण के लिए जेजेबी को वापस भेज दिया गया। मामले में सबसे बड़ा विवाद आरोपित की जन्मतिथि को लेकर है। आरोपित पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्कूल रिकार्ड में उसकी जन्मतिथि 7 अक्टूबर 2011 दर्ज बताई गई है, जिसके आधार पर घटना के समय उसे नाबालिग माना जा सकता है।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और ईवी का दबदबा बढ़ा

नई दिल्ली 12 जून (निस) इस साल जनवरी से मई के दौरान दिल्ली में इलेक्ट्रिक दो पहिया और प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण 2019 के बाद सबसे ज़्यादा रहा है। जबकि इसी दौरान ई-रिक्शा का पंजीकरण सात साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। रिसर्च और एडवाइज़री थिंक टैंक एनवायरोकैटलिस्ट्स के जारी डेटा के अनुसार पता चला कि दिल्ली के ईवी मार्केट में इलेक्ट्रिक दो पहिया का दबदबा रहा है। इस साल के पहले पांच महीनों में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में इनकी हिस्सेदारी 51.9 प्रतिशत रही।

छत्तीसग? में निवेश के लिए बिछा रेड कारपेट, 9,580 करो? रुपये के मिले प्रस्ताव

रायपुर 12 जून (निस) छत्तीसग? ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसग? इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सात प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करो? रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसग? में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसग? तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए 'रेड कारपेट' बिछा हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसग? के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन सहित दक्षिण भारत के कई ब? उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करो? रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसग? आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है। राज्य में उद्योगों के लिए आसान प्रक्रियाएं, सिंगल विंडो व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और उद्योग अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसग? में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद ने आईटी, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसग? भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे ब? रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसग? देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसग? सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करो? से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। रेलवे नेटवर्क, भारतमाला परियोजना, एयर कार्गो सुविधाओं तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता उद्योगों के लिए इसे अत्यंत अनुकूल बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसग? देश में ग्रीन स्टील को ब?वा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को 3.5 लाख करो? रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश देश के प्रमुख पावर हब के रूप में उभर रहा है।

किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 9 सूत्रीय मांगपत्र

बेमेतरा 12 जून (निस) जिले में खरीफ सीजन से पहले किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला किसान कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांगपत्र कलेक्टर को सौंपा। प्रदर्शन में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे, पूर्व विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंगत साहू सहित महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले किसान खाद, बीज, बिजली और सिंचाई जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि समय पर समाधान नहीं होने से खेती-किसानी प्रभावित हो रही है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस द्वारा सौंपे गए 9 सूत्रीय मांगपत्र में प्रति एकड़ खाद कटौती की व्यवस्था समाप्त करने, सभी किसानों को एकमुश्त खाद वितरण सुनिश्चित करने, डीजल की पर्याप्त उपलब्धता कराने, कृषि बिजली दरों में राहत देने, खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने, किसान क्रेडिट कार्ड (चष्टष्ट) की ऋण सीमा बढ़ाने, धान खरीदी की राशि का एकमुश्त भुगतान करने तथा लंबित अनुदान राशि जल्द जारी करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।

पैदल जा रही महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश

अंबरनाथ, 12 जून (निस) अंबरनाथ पश्चिम क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। सब्जी खरीदकर घर लौट रही 41 वर्षीय महिला के गले से दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता संध्या मनीष पिल्ले (41 वर्ष) अंबरनाथ पश्चिम स्थित कोहोजगांव के पनवेलकर गार्डन परिसर में रहती हैं। 10 जून की शाम करीब 7.15 बजे वह शिफा हॉस्पिटल के सामने से सब्जी खरीदकर पैदल अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान पीछे से काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात युवक उनके पास पहुंचे। बताया गया है कि बाइक चला रहे आरोपी ने चॉकलेटी-मेहंदी रंग की शर्ट, ग्रे रंग की पैंट पहन रखी थी और चेहरे पर नीले रंग का रूमाल बांधा हुआ था। वहीं पीछे बैठे आरोपी ने सफेद और ग्रे डिजाइन वाली शर्ट तथा काले रंग की पैंट पहन रखी थी। महिला जब तक कुछ समझ पातीं, उससे पहले पीछे बैठे आरोपी ने उनके गले से सोने की चेन को जोरदार झटका देकर छीन लिया।

अमृतपाल सिंह प्रिंटर, पब्लिशर व संपादक ने जेएसडी पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए आईजी प्रिंटर्स प्रा.लिमि., 104, डीएसआईडीसी, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-20 के मालिक/कीपर जगपाल सिंह से छपवा कर कार्यालय दैनिक भारत देश हमारा 24/34 तिलक नगर नई दिल्ली से प्रकाशित किया।
PRGI (RNI) Regd. No.57282/1994

CHARDIKLA TIME TV
24X7 INFOTAINMENT CHANNEL
SCAN TO DOWNLOAD OUR APP
SCAN TO WATCH LIVE
Available FREE! at following Platforms
TATA PLAY CH. NO. 1945
DD Free Dish CH. NO. 340
VIDEOCON d2h CH. NO. 779
airtel digital TV CH. NO. 557
dishtv CH. NO. 1152
in digital CH. NO. 581
Jio TV
Available Worldwide on
in USA sling TELEVISION
dish CH. NO. 748-008
amazon fireTV
YouTube
TikTok
Roku TV
eBaba Ent
SMART STB
TANGO TV
FREE TV
MOBI FREE TV
EKOM FLIX
CHARDIKLA MN MEDIA NETWORK
Also available on Social Media @
/Chardikla Time TV
/CK Time TV North America
/Chardikla Time TV Live
ceo@cktimetv.com
www.timetv.news
www.cktimetv.com